



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939

No. 15]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(रक्षोपाय महानिदेशालय)

(सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद कर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2018

**विषय :** मोड्यूल अथवा पेनल्स में जुड़े हुये या बिना जुड़े सोलर सेल्स के भारत में आयात से संबंधित रक्षोपाय जाँच के प्रारम्भिक परिणाम। सीमा शुल्क प्रशुल्क नियम 1975 एवं सीमा शुल्क अधिनियम (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आंकलन) 1997 के तहत कार्यवाही के संदर्भ में।

**सा.का.नि. 16(अ).—(क) परिचय**

सीमा शुल्क प्राशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आंकलन) के नियम 5 के अंतर्गत इस कार्यालय में दिनांक 05/12/2017 को मैसर्स इंडियन सोलर मैनुफ्रेक्चरर्स असोसिएशन (आई एस एम ए) द्वारा 5 भारतीय उत्पादकों (i) मैसर्स मुन्द्रा सोलर पी वी लिमिटेड, अदानी हाउस, मीठा खली 6 रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380009, गुजरात ; (ii) मैसर्स इंडोसोलर लिमिटेड, 3सी/1, ईको टेक-II, उद्योग विहार, डिस्ट्रिक्ट: गौतम बुध नगर, ग्रेटर, नोएडा- 201306, उत्तर प्रदेश (iii) मैसर्स ज्यूपिटर सोलर पावर लिमिटेड, विल्लेज कथा, पोस्ट ऑफिस बड्डी, तेह. नालागढ़, डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश- 173205; (iv) मैसर्स वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, फाल्टा एस ई जेड सैक्टर- II, फाल्टा डिस्ट्रिक्ट 24 साउथ प्रगानस, वेस्ट बंगाल- 743504 ; (v) मैसर्स हिलिओस फोटो वोल्टैक लिमिटेड, 43 बी, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेस- III, नई दिल्ली- 110020 की ओर से मैसर्स एथेना लॉ असोसिएशन के माध्यम से “मोड्यूल अथवा पैनल में जुड़े अथवा अलग सोलर सेल्स जिसे यहाँ विचाराधीन उत्पाद (पियूसी) के नाम से संबोधित किया गया है के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लागू करे जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिससे विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा वाली वस्तुओं के वर्धित आयात से हुई गंभीर क्षति अथवा उसकी आशंका से बचाया जा सके। आवेदकों ने दावा किया है कि पियूसी के आयात में बढ़ोतरी के कारण कई घरेलू उत्पादकों ने अपनी उत्पादन सुविधाओं को लगभग निष्क्रिय रखा है और भारी नुकसान ने घरेलू उद्योग को अपंग कर दिया है। इस कारण से, आवेदकों ने भी क्षति को कम करने के लिए एक अंतिम रक्षोपाय शुल्क को लागू करने का अनुरोध किया है

**(ख) अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया**

(2) आवेदनों की जांच और साथ में प्रेषित प्रमाण/विवरण और दस्तावेजों की जांच करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आवेदन कथित नियम के नियम 5 की अपेक्षाओं को पूर्ण करता है। अतः दिनांक 19.12.2017 के NOI के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद के भारत में आयात हेतु रक्षोपाय जाँच की शुरुआत की गई। रक्षोपाय जाँच की शुरुआत का नोटिस दिनांक 19.12.2017 को भारत के राजपत्र असाधारण में GSR संख्या 1522 में प्रकाशित किया गया।

(3) कथित नियम के नियम 6 के उप नियम (2) और 3 के अनुसार दिनांक 19.12.2017 को रक्षोपाय जाँच की शुरुआत का नोटिस और दिनांक 28.11.2017 को घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर गैर गोपनीय संस्करण की एक प्रति केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत के दूतावासों के माध्यम से प्रमुख निर्यातक देश की सरकारों को और आवेदन में विवरित संबद्ध पार्टियों को अग्रेषित की गई। इसके अतिरिक्त कथित नियम के 6(4) के तहत निर्धारित निर्यातक / आयातकों / घरेलू उत्पादकों द्वारा भरी जाने वाली प्रश्नावली को अपने संबद्ध पार्टियों को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित किया गया कि वह अपने विचार जाँच कि शुरुआत के 30 दिन में लिखित में प्रस्तुत करें।

(4) दिनांक 20.12.2017 को घरेलू सोलर सेल्स के उत्पादक (i) मैसर्स इंडियन सोलर मेनूफैक्चर्स असोसिएशन और (ii) मैसर्स सोलर पावर डिवेलपर असोसिएशन को दिनांक 19.12.2017 का जाँच की शुरुआत की प्रति, 28.11.2017 कि गैर गोपनीय संस्करण का प्रार्थना - पत्र और निर्यातक, आयातक एवं घरेलू उत्पादकों द्वारा भरे जाने वाली प्रश्नावली की प्रति भेजी गई।

#### (क) टिप्पणियाँ

(5) मैंने घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर आवेदन, यथावत प्रमाणित वित्तीय एवं अन्य अभिलेखों को बहुत सावधानी से जाँचा है। मॉड्यूल अथवा पेनल्स में जुड़े हुए अथवा बिना जुड़े सोलर सेल्स के भारत में वर्धित आयात से हो रही गंभीर क्षति से घरेलू उत्पादकों को बचाने के संदर्भ में मेरे द्वारा रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के संदर्भ में मौजूदा जाँच के प्रसंगोचित विभिन्न घटकों के ऊपर मेरी जो प्रारम्भिक टिप्पणियाँ हैं वह निम्नानुसार हैं-

#### 5.1 विचाराधीन उत्पाद (PUC)

5.1.1 विचाराधीन उत्पाद मॉड्यूल अथवा पेनल्स में जुड़े हुए अथवा बिना जुड़े सोलर सेल्स टैरिफ शीर्ष 8541 और टैरिफ 85414011, 1975 के सीमा शुल्क प्रशुल्क नियम के अंतर्गत वर्गीकृत है। सोलर सेल्स को व्यावसायिक भाषा में फोटोवोल्टिक सेल्स भी कहा जाता है फोटोवोल्टिक तकनीक परमाणु स्तर पर सूर्य के प्रकाश को विद्युत शक्ति में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित करने में समर्थ करता है। सोलर सेल्स ठोस विद्युत उपकरण हैं जो फोटोवोल्टिक क्रिया से सूर्य के प्रकाश को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करते हैं।

सोलर सेल्स की व्यावहारिकता हेतु उसे पैनल अथवा मॉड्यूल में रखा गया है। दूसरे शब्दों में सोलर पैनल / मॉड्यूल सोलर सेल्स की फिटिंग है। सोलर सेल्स में विद्युत कनेक्शन को सीरीज़ में जोड़ा जाता है जिससे वांछित वाट अथवा वांछित विद्युत प्रवाह का उत्पादन किया जा सके।

5.1.2 विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन हेतु दो प्रमुख तकनीकों का प्रयोग किया जाता है - पहली तकनीक का नाम क्रिस्टलाईन सिलिकॉन (c-Si) तकनीक है जिसे सिलिकॉन वेफ़र तकनीक भी कहा जाता है।

क्रिस्टलाईन सिलिकॉन में एन- टाईप, पी- टाईप, मोनो क्रिस्टलाईन और मल्टी क्रिस्टलाईन सिलिकॉन पदार्थ शामिल हैं। दूसरी तकनीक 'थिन फिल्म' तकनीक कहलाती है जिसमें, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन, कैडमियम टेल्लुरियम (सीडीटीई) अथवा कॉपर इंडियन गेलियम सिलिनियम का प्रयोग अर्धचालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। दोनों c-Si तकनीक और 'थिन फिल्म' तकनीक से बने सोलर सेल्स का आयात भारत में किया जाता है।

5.1.3 - आवेदक का दावा है कि वह सोलर सेल्स / पैनल मॉड्यूल का उत्पादन थिन फिल्म तकनीक से नहीं बल्कि c-Si तकनीक से करते हैं। आवेदकों का दावा है कि c-Si तकनीक और थिन फिल्म तकनीक से बने सोलर सेल्स का प्रयोग सोलर विद्युत कारखानों में किया जाता है। आवेदकों के अनुसार जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन और राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाएं दोनों तकनीकों में ना ही कोई भेद करती हैं ना ही अलग-अलग नीलामी दरों का अधिनिर्णय करती हैं। साथ ही दोनों ही तकनीक से बने सोलर सेल्स में कोई अंतर नहीं है और दोनों के अंतिम प्रयोग एक ही है। अतः आवेदकों का दावा है कि सोलर सेल्स का c-Si तकनीक से घरेलू उत्पादन आयातित सोलर सेल्स जो कि c-Si तकनीक अथवा 'थिन फिल्म' तकनीक का प्रयोग करते हुए बनाया गया है, एक जैसे उत्पाद हैं और यह आयातित उत्पाद के साथ प्रत्यक्ष स्पर्धा में आते हैं।

#### 5.2 घरेलू उद्योग

5.2.1 सीमा शुल्क प्रशुल्क नियमावली 1975 का अनुच्छेद 8B कि उपधारा (6) के परिच्छेद b घरेलू उद्योग को इस प्रकार वर्णित करता है ख) घरेलू उद्योग का अर्थ है -

(i) भारत में उसी उत्पाद अथवा प्रत्यक्ष स्पर्धा में आ रहे उत्पाद के उत्पादक

(ii) ऐसे उत्पादक जिनका उसी वस्तु का सामूहिक उत्पादन अथवा सीधे प्रतिस्पर्धा में आ रही वस्तु, भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा हो।

5.2.2 विचाराधीन उत्पाद के आवेदकों द्वारा यह दावा किया गया है कि इनकी फर्म का कुल उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से भी अधिक है जैसा कि नीचे सारणी में विवरित है। आवेदकों का दावा है कि उनका कुल उत्पादन विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन के एक बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिये वर्तमान आवेदन दायर करने का उनका आधार बनता है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2018 तक)	2017-18 वार्षिक
कुल भारतीय उत्पादन	मे वा	246	305	798	544	1164
आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग का उत्पादन	मे वा	237	295	473	381	838
भारतीय उत्पादन में घरेलू उद्योग का कुल भाग	%	96	97	59	70	72

5.2.3 रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना का ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जा सकता है कि आवेदकों का कुल उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का मुख्य भाग है। तदनुसार, सीमा शुल्क प्रशुल्क नियमावली 1975 के अनुच्छेद 8B की उप धारा (6) के परिच्छेद b के अनुसार यह आवेदक घरेलू उद्योग का गठन करते हैं।

5.2.4 घरेलू उद्योग के आवेदकों का निर्धारण करते हुए यह पाया गया कि मैसर्स मुन्द्रा सोलर पी वी लिमिटेड, मैसर्स वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड और मैसर्स हीलिओस फोटो वोल्टैक लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र में आते हैं (SEZ)। विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबन्धित योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की निर्यात वृद्धि योजना है। यह योजना निर्यात को बढ़ाने के आशय से इकाईयों को कुछ वित्तीय और गैर राजकोषीय लाभ प्रदान करती है। तथापि, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयाँ भारत में दूसरे घरेलू उत्पादन इकाईयों की तरह घरेलू नियम (कभी-कभी कुछ छूट के साथ) रोजगार पैदा करना है और घरेलू बिक्री इत्यादि बिन्दुओं का अनुपालन करते हैं। अतः किसी भी वस्तु का वर्धित आयात जो घरेलू उत्पाद को क्षति पहुँचा सकता है, विशेष आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रही इकाईयों अथवा उससे भिन्न इकाईयों को एक जैसे ही प्रभावित करता है। अतः विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयाँ घरेलू उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अन्य सभी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की इकाईयाँ जो इसी उत्पाद या प्रत्यक्ष स्पर्धा में आ रहे उत्पादन में शामिल हैं वह भी घरेलू उद्योग की परिधि में शामिल हैं।

### 5.3 जाँच की अवधि

5.3.1 सीमा शुल्क प्रशुल्क 1975, कथित नियम और GATT का अनुच्छेद XIX और विश्व व्यापार संगठन का रक्षोपाय समझौता, जाँच की अवधि को न ही परिभाषित करता है और ना ही इस संदर्भ में कोई मार्गदर्शन देता है। तथापि यह स्पष्ट है कि जाँच की अवधि पर्याप्त रूप से लम्बी और हाल ही के समय की हो जिससे विभिन्न प्रारम्भिक कारकों जैसे घरेलू बाज़ार की स्थिति, घरेलू उद्योग का प्रदर्शन इत्यादि के आधार पर यह तय किया जा सके कि वर्धित आयात के कारण घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच रही है अथवा नहीं और क्या रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण तर्कसंगत है। इस आधार पर, वर्तमान मामले में यह उचित माना जाता है कि जाँच की अवधि 2014-15 से 2017-18 (वार्षिक) मानी जाए।

### 5.4 सूचना का स्रोत

5.4.1 विचाराधीन उत्पाद के संबंध में लेन- देन के आधार पर डेटा निम्न इकाईयों से लिया गया है –

(i) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार से वर्ष 2014-15 और वर्ष 2017-18 कि पहली तिमाही के अंत की अवधि और (ii) मैसर्स इनफोड्राईव इंडिया नई दिल्ली से 2017-18 की दूसरी तिमाही (जुलाई 2017 से सितम्बर 2017) की अवधि से 2014-15 से 2017-18 (सितम्बर 2017 तक) की अवधि तक का घरेलू उद्योग के संबंध में सदृश आँकड़े आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए और (i) मूल्य परीक्षण रिपोर्ट, (ii) वित्तीय अभिलेख , (iii) उत्पादन, बिक्री, माल सूची से संबन्धित अन्य रिकॉर्ड के आधार पर उनकी पुष्टि की गई है। जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 की अवधि के आयात के आँकड़े डीजीसीआई और एस, वाणिज्य मंत्रालय, कोलकाता से मंगवाया गया है। 2014-15 से 2017-18 (जुलाई 2017) तक के घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किये गये आयात के आँकड़े और जुलाई 2017 से सितम्बर 2017 तक के डीजीसीआई और एस से प्राप्त आयात आँकड़ों को विश्लेषण हेतु लिया गया है।

### 5.5 प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता –

5.5.1 - घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में गोपनीय आधार पर कुछ जानकारी प्रदान की है और अनुरोध किया है कि इसे गोपनीय माना जाएगा। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में गोपनीय आधार पर कुछ जानकारी प्रदान की है और अनुरोध किया है कि इसे गोपनीय माना जाएगा। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन का एक गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी) भी प्रदान किया है, जो फाइल नं. डी 22011/75 के तहत महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा जारी किए गए 21.12.2009 के ट्रेड नोटिस के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 7 के तहत आवश्यक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने इस जानकारी की गोपनीयता के दावे को न्यायसंगत ठहराया है।

5.5.2 – उक्त नियमों के नियम 7 के संदर्भ में आवेदक गोपनीय सूचना का खुलासा न करने का निर्णय ले सकता है अथवा गैर गोपनीय सारांश प्रस्तुत कर सकता है। घरेलू उद्योग द्वारा सूचना कि गोपनीयता बनाए रखने के कारण प्रस्तुत किए गए हैं और सूचना का गैर गोपनीय सारांश को गोपनीयता के आधार पर प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग द्वारा बताए गए कारणों कि सावधानीपूर्वक जाँच के बाद मुझे लगता है कि यह कारण कथित नियम के नियम 7 की आवश्यकताओं को पूर्णतः संतुष्ट करता है अतः आवेदक द्वारा गोपनीयता कि माँग को स्वीकार किया जाता है।

### 5.6 पूर्ण रूप (absolute terms) में वर्धित आयात

5.6.1 विचाराधीन उत्पाद विभिन्न देश जैसे चीन लोक गणराज्य, मलेशिया, सिंगापुर और ताईवान से भारत में आयात किया जा रहा है। विचाराधीन उत्पाद का एक महत्वपूर्ण भाग चीन लोक गणराज्य से आयात किया जा रहा है। जैसा कि देखा गया विचाराधीन उत्पाद के आयात का आयतन वर्ष 2014-15 में 1275 मेगावाट से वर्ष 2017-18 में 9474 मेगावाट (वार्षिक) पहुँचा। यह 2014-15 से वर्ष 2017-18 वार्षिक का 643 प्रतिशत बढ़ोतरी है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक वर्ष आयात की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है। इसके अलावा वर्ष 2017-18 के पहले छः महीनों में आयात की मात्रा में अचानक वृद्धि हुई है, जो कि वर्ष 2016-17 की 74 प्रतिशत है। विचाराधीन आयात की वर्ष 2014-15 से 2017-18 (वार्षिक) की पूर्ण रूप एवं प्रतिशत रूप में बढ़ती हुई मात्रा को तालिका के माध्यम से नीचे दर्शाया गया है :-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 सितंबर 2017	2017-18 वार्षिक
कुल आयात	में वा	1275	4186	6375	4737	9474
पिछले वर्षों की तुलना में आयात प्रतिशत में वृद्धि	%	--	228	52	-	49

### 5.7 वर्धित आयात- सापेक्ष में (in relative terms)

5.7.1 घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में विचाराधीन उत्पाद के आयात में वर्ष 2014-15 से 2017-18 के बीच लगातार बढ़त देखी गई। घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में इस तरह की आयात वृद्धि दर बीच की अवधि 2015-16 के दौरान 1371 प्रतिशत थी। यहाँ तक कि विचाराधीन उत्पाद का आयात घरेलू उत्पादन के सापेक्ष में वर्ष 2014-15 में 519% से वर्ष 2017-18 में 814% की बढ़त दर्ज की गई। इसी प्रकार जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन के मुकाबले विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 सितंबर 2017	2017-18 वार्षिक
कुल आयात	मे वा	1275	4186	6375	4737	9474
भारतीय उत्पादन		246	305	798	544	1164
भारत के उत्पादन में आयात का प्रतिशत	%	519	1371	799	871	814

## 5.8 अप्रत्याशित प्रगति

5.8.1 न ही सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 वी और ना ही उसके अधीन बने नियमों के तहत रक्षोपाय महानिदेशालय को उन अप्रत्याशित घटनाओं का विश्लेषण करने को बाध्य करता है जिसके तहत आयात में वृद्धि पाई गई है। कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे कोई प्रावधान नहीं हैं जिनसे अप्रत्याशित घटनाओं का सत्यापन किया जा सके। न ही वह ऐसे कोई उपाय निर्दिष्ट करते हैं जिनका पालन करते हुए इन अप्रत्याशित घटनाओं का विश्लेषण किया जा सके। फिर भी गैट के अनुच्छेद XIX के साथ संलग्न रक्षोपाय के संदर्भ में विश्व व्यापार संगठन का सम्झौता, राष्ट्रीय प्राधिकारणों को वर्धित आयात के चलते घरेलू उत्पादकों को ही गंभीर क्षति के संबंध में अप्रत्याशित घटनाओं की जांच करने को बाध्य करता है। इन आवश्यकताओं के मद्देनजर यह महानिदेशालय लगातार अप्रत्याशित बढ़त की जांच कर रहा है। अतएव प्रस्तुत मामले की भी अप्रत्याशित बढ़त के संदर्भ में जांच की जानी उचित होगी जिसके चलते विचाराधीन उत्पाद की वर्धित आयात जांच की अवधि के दौरान पाया गया। ऐसा करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि “अप्रत्याशित घटनाओं या परिस्थितियों के घटक को सराहा जाये और उसको विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय अंग के फैसलों के संदर्भ में समझा जाये।”<sup>1</sup>

5.8.2 अर्जेंटीना फुटवेयर केस के मामले में विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय अंग का मानना था की वर्धित आयात के चलते घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति “अप्रत्याशित” होगी। उस केस में यह भी नोट किया गया था की गैट पैनल की यह धारणा है कि वर्धित आयात “अप्रत्याशित घटना” है। उसी प्रकार कोरिया डेरी<sup>2</sup> के मामले में भी विश्व व्यापार संगठन के अपीलीय अंग द्वारा यह माना गया कि अप्रत्याशित घटनाएँ वह घटनाएँ हैं जो पूर्वदृष्ट न हों। एक अन्य US स्टील<sup>3</sup> के केस में रक्षोपाय पैनल द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि कई गतिविधियाँ मिल का अप्रत्याशित घटनाओं को पैदा करती हैं। यह भी नोट किया गया कि वर्धित आयात कई बार अप्रत्याशित घटनाओं का परिणाम हो सकता है। यह अप्रत्याशित घटनाएँ ही हैं जिनके परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हुई है। यह भी पाया गया कि अप्रत्याशित घटनाएँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन्हें वास्तविक मामले के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।<sup>4</sup>

5.8.3 उपर्युक्त निष्कर्षों को वर्तमान केस पर लागू करने पर, यह स्पष्ट है की पीयूसी के आयातों में अस्थायी वृद्धि जिसके कारण कथित रूप से डीआई को गंभीर क्षति कारित हो रही है अथवा ऐसी गंभीर क्षति की संभावना बढ़ रही है, अप्रत्याशित अथवा अनपेक्षित और तथ्यात्मक होनी चाहिए। जबकि आयातों के डेटा के आधार पर वर्धित आयातों की घटना अपने आप में प्रत्यक्ष होनी चाहिए, इसके अप्रत्याशित अथवा अनपेक्षित होने का निष्कर्ष प्रासंगिक होना चाहिए। वर्तमान केस में, इसका संगत सन्दर्भ वह घटना अथवा घटनाएँ होंगी जिनके कारण भारत में पीयूसी के आयातों पर टैरिफ रियायत कारित हुई है। दूसरे शब्दों में, पीओआई के दौरान वर्धित आयातों का तथ्य दायित्व लेते हुए अर्थात् विश्व व्यापार संगठन में परिग्रहण, विभिन्न विश्व व्यापार संगठन करारों के अधीन प्रतिबद्धताओं का पालन करने का संकल्प करते हुए, टैरिफ रियायत प्रदान करते हुए और परिणामस्वरूप 13 दिसंबर, 1996 को घोषित सूचना प्रोद्योगिकी उत्पादों (आईटीए-1) पर मंत्रालयी घोषणा के माध्यम से उन टैरिफ रियायतों में संशोधन करते हुए, अप्रत्याशित अथवा अनपेक्षित होना चाहिए।

5.8.4 इस निर्धारण के सन्दर्भ में की, क्या पीओआई के दौरान पीयूसी के आयातों में तेज और महत्वपूर्ण वृद्धि की वर्तमान गतिविधि वास्तव में अप्रत्याशित अथवा अनपेक्षित गतिविधि है, आवेदकों द्वारा दिए गए साक्ष्यों की जांच की गई है और उसके निष्कर्ष निम्नानुसार है:

(i) चीन ने में सौर सेल्स की 11.12 जीडब्ल्यू की अपनी उत्पादन क्षमता को दुगुना कर 2016 में 27.78 जीडब्ल्यू कर लिया है। इसी प्रकार, सौर मोड्युल्स की उत्पादन क्षमता को 2012 में 12.46 जीडब्ल्यू से बढ़ाकर 2016 में 35.47 जीडब्ल्यू कर लिया है। इसके अतिरिक्त, चीन में 35 उत्पादक जो की समग्र रूप से सौर सेल्स का 57% और सौर मोड्युल्स 67% का उत्पादन करते हैं, का डेटा अतिरिक्त क्षमता व्यक्त कर है, जैसा की निम्न तालिका में दर्शाया गया है। अतिरिक्त क्षमता के साथ विशाल उत्पादन क्षमता के होने का प्रभाव आवेदकों के मामलों पर है की चीन<sup>5</sup> से पीयूसी के आयातों में तेज वृद्धि हुई है।

<sup>1</sup> एपीलेट बॉडी रिपोर्ट, अर्जेंटीना- फूटवेयर (EC), पैरा, 91; एपीलेट बॉडी रिपोर्ट, कोरिया- डायरी, पैरा 84

<sup>2</sup> पैनल रिपोर्ट, डोमिनिकन रिपब्लिक- सेफगार्ड मेज़र, पैरा 7.133।, एपीलेट बॉडी रिपोर्ट, भी देखें।  
अर्जेंटीना- फूटवेयर (EC), पैरा, 96 और कोरिया- डायरी, पैरा 89 जिसमें गैट वर्किंग पार्टी रिपोर्ट- US को में देखा जा सकता है, फर फेल्ड हैट्स, 22 अक्टूबर 1951

<sup>3</sup> पैनल रिपोर्ट, डोमिनिकन रिपब्लिक- सेफगार्ड मेज़र, पैरा 7.133।, एपीलेट बॉडी रिपोर्ट, भी देखें।  
अर्जेंटीना- फूटवेयर (EC), पैरा, 96 और कोरिया- डायरी, पैरा 89 जिसमें गैट वर्किंग पार्टी रिपोर्ट- US को में देखा जा सकता है, फर फेल्ड हैट्स, 22 अक्टूबर 1951

<sup>4</sup> एपीलेट बॉडी रिपोर्ट, US - स्टील सेफगार्ड, पैरा 315

<sup>5</sup> क्रिस्टलीन सिलिकॉन फोटोवोल्टिक सैल्स के विरुद्ध सेक्शन 201 कार्यवाहियों में यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड कमिशन (यूएसआईटीसी) के निष्कर्ष (अन्य उत्पादों में चाहे आंशिक रूप से चाहे पूर्ण रूप से इकट्ठे किए गए हों अथवा नहीं)

सौर सेल्स					
जीडब्ल्यू में	2012	2013	2014	2015	2016
क्षमता (सेल्स)	16.70	19.30	22.19	26.46	33.13
उत्पादन (सेल्स)	11.12	14.03	18.54	22.72	27.78
घरेलू खपत	10.68	13.06	17.31	22.26	26.76
निर्यात	0.40	0.81	0.87	0.52	0.50
अप्रयुक्त क्षमता	33.41%	27.31%	16.49%	14.13%	16.15%
सौर मोडयुल्स					
क्षमता (सौर मोडयुल्स)	20.13	22.77	27.99	34.71	46.40
उत्पादन (सौर मोडयुल्स)	12.46	16.32	22.07	28.79	35.47
घरेलू खपत	2.46	5.94	7.73	12.86	20.69
निर्यात	9.61	10.39	13.64	15.62	13.93
अप्रयुक्त क्षमता	38.10%	28.32%	21.15%	17.05%	23.99%
उत्पादन पर निर्यात	77.12%	63.66%	61.80%	54.25%	39.27%

(ii) पीयूसी के संबंध में चीन का निर्यात अभिविन्यास निर्विवाद है, लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है कि पिछले दो वर्षों के दौरान, इसकी दिशा और व्यापार निर्यात की मात्रा भारत की ओर महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित हुई है। उदाहरणार्थ, जबकि 2012 में चीन का भारत को निर्यात इसके कुल वैश्विक निर्यातों का नगण्य प्राय 1.52% था, यह 2016 में बढ़कर 21.58% हो गया। [www.trademap.org पर उपलब्ध]

को चीनी निर्यात (यूएसडी 000')	2012	2013	2014	2015	2016
विश्व	12,775,263	10,150,759	12,319,183	12,938,427	11,347,462
जापान	892,923	2,794,236	4,394,922	3,341,833	2,558,724
भारत	193,756	510,278	488,619	1,356,754	2,448,216
यूएसए	1,416,963	1,208,074	1,818,175	1,634,799	1,368,664
यूरोपियन यूनियन	8,283,128	2,914,197	2,352,842	2,054,177	1,288,605
भारत का हिस्सा	1.52%	5.03%	3.97%	10.49%	21.58%
ईयू+यूएसए का हिस्सा	75.93%	40.61%	33.86%	28.51%	23.42%

(iii) पीयूसी के भारत में चीनी निर्यातों की दिशा में उपर्युक्त परिवर्तन बिल्कुल हालिया समय के डेटा से पुनर्पुष्ट होता है। जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है, 2016 की प्रथम छमाही (एच1 2016) में, भारत को चीनी निर्यात इसके कुल निर्यातों का 18.51% था, जिसकी तुलना में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसका संयुक्त निर्यात 30.65% था (इसके कुल निर्यातों का)। स्थिति अगली दो छमाहियों की अवधि में नाटकीय रूप से बदल गई। 2016 की द्वितीय छमाही (एच2 2016) में, भारत को चीनी निर्यात 25.09% था जबकि यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को इसका निर्यात गिरकर 15.12% हो गया। पुनः, 2017 की प्रथम छमाही में (एच1 2017, चीन का भारत को निर्यात इसके कुल निर्यात का बढ़कर चौथा देने वाला 30.65% हो गया जबकि ईयू और यूएसए को इसका निर्यात गिरकर इसके कुल निर्यात का 5% रह गया। व्यापार के इस पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसमें चीन ने विकसित देशों/बाजारों जैसे ईयू और यूएसए आदि की तुलना में भारतीय बाजार को और अधिक तीव्रता से लक्षित करना शुरू कर दिया है, प्रत्याशित नहीं सकता।

को चीनी निर्यात (यूएसडी 000')	एच1 2016	एच2 2016	एच1 2017
विश्व	6,062,679	5,284,783	5,350,966
भारत	1,122,083	1,326,133	2,074,573
जापान	1,219,493	1,339,231	1,095,773
ईयू	838,606	450,002	233,481
यूएसए	1,019,870	348,793	34,268
भारत का हिस्सा	18.51%	25.09%	38.77%
ईयू+यूएसए का हिस्सा	30.65%	15.12%	5.00%

5.8.5 दूसरी अनपेक्षित गतिविधि जिसके कारण पीयूसी के भारत में आयातों में वृद्धि हुई और विदेशी बाजारों से इसका शिफ्ट हुआ, ईयू और यूएसए द्वारा चीनी निर्यातों पर लगाए गए व्यापार उपाय प्रतिबंध थे। आदेशित प्रतिपाटन और प्रतिकारक ड्यूटी यूएसए से (i) क्रिस्टालाइन सिलिकॉन फोटोवोल्टैक (सीएसपीवी 1) जांच 07.12.2012 को प्रभावी हो गई और (ii) सीएसपीवी 2 जांच 05.06.2013 को प्रभावी हो गई थी, से संबंधित थी। ईयू में भी अंतिम उपाय 05.06.2013 से प्रभावी हो गए [04.06.2013 का कमिशन रेग्यूलेशन (ईयू) संख्या 513/2013] और अंतिम उपाय 05.12.2013 को लागू किए गए थे [02.12.2013 का कमिशन रेग्यूलेशन (ईयू) संख्या 1238/2013]। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अधीन घरेलू कंटेंट अपेक्षाओं (डीसीआर) के कारण इन उपायों का तत्काल प्रभाव भारत में गोचर नहीं था। अतः, डीआई को डीसीआर द्वारा आदेशित सीमा तक निष्क्रिय घरेलू बाजार का आश्वासन था। तथापि, 2013 में, यूएसए ने जेएनएनएसएम के अधीन डीसीआर को विश्व व्यापार संगठन विवाद समझौता बॉडी के समक्ष चुनौती दी और इसका परिणाम यह था कि अक्तूबर, 2016 में, विश्व व्यापार संगठन अपीलीय बॉडी ने डीसीआर को टीआरआईएम के करार के अनुच्छेद 2.1 और जीएटी 1994 के अनुच्छेद III:4 के असंगत ठहराया था। अतः भारत ने डीसीआर को वापस ले लिया। डीसीआर को वापस लेने के अनुवर्तन में, महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन और अधिक प्रोनाउंस हो गए हैं। जैसा उक्त कथित है, ये गतिविधियां प्रत्याशित नहीं हो सकी।

5.8.6 2015 में, ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के लिए, भारत ने 2005 के स्तर से कार्बन डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन में 33-35% की कमी लाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर पेरिस करार में प्रतिबद्धता जताई थी। इस करार के अनुसरण में, भारत ने वर्ष 2022 तक 100 जीडब्ल्यू सौर उर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस प्रतिबद्धता के कारण भारत में सौर उर्जा जनरेशन प्रोजेक्टों की मांग में वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि पेरिस करार जो कि 197 देशों द्वारा हस्ताक्षरित है (आज की तारीख 172 देशों द्वारा पुष्ट) के अधीन भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता, 13 दिसम्बर, 1996 को आईटीए-1 के अधीन पीयूसी के लिए स्वीकारी गई आयात टैरिफ रियायत के समय अप्रत्याशित थी। इसी प्रकार, संक्षिप्त समय अवधि में भारत में पीयूसी की मांग में बहुत वृद्धि हुई जिसके कारण आयातों में उछाल आया अनपेक्षित थी।

5.8.7 दूसरा संगत कारक जो उभर कर आया है वह यह है कि पीयूसी का आयात बहुत कम कीमतों पर हो रहा है; जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है, आयातित पीयूसी की लैंडेड वैल्यू में अचानक और काफी कमी हुई है। इसका तात्कालिक प्रभाव यह हुआ है कि घरेलू उद्योगों के उत्पादों की बिक्री में कमी हुई। अतः लगातार गिरती लैंडेड वैल्यू पर आयातों में आए उछाल ने आयातों और घरेलू उत्पादन के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक संबंध को परिवर्तित कर दिया है, जिसका नुकसान घरेलू उद्योग को हुआ है। इसने डीआई की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता, पीयूसी के उत्पादन और बिक्री की क्षमता में बाधा डाली है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धात्मक संबंध में हुआ यह परिवर्तन पूर्ण रूप से अनपेक्षित था।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितम्बर, 2017 तक)	2017-18 (वार्षिक)
आयातों की लैंडेड वैल्यू						
सौर सैल्स	रू./वाट	18.78	18.81	15.42	14.04	14.04
सौर मॉड्युल्स	रू./वाट	36.95	36.18	29.20	24.77	24.77
Net sales realisation of Domestic Industry						
सौर सैल्स (इंडेक्स)	रू./वाट	100	94	88	62	62
सौर मॉड्युल्स (इंडेक्स)	रू./वाट	100	103	82	92	92

5.8.8 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क टैरिफ मद 85414011 के अधीन आने वाले पीयूसी पर भारत का आयात टैरिफ 'निशुल्क' है। यह 'निशुल्क' टैरिफ दिनांक 13 दिसम्बर, 1996 को सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर मंत्रालयी घोषणा (इसमें इसके बाद उसे "आईटीए-1" भी कहा गया है) के साथ पठित जीएएटी 1994 के अधीन और इसके अंतर्गत टैरिफ रियायतों सहित भारत की बाध्यताओं के अनुवर्तन में समाविष्ट किया गया था। पीयूसी आईटीए-1 के खंड 1, अनुलग्नक ए के अधीन आता है। आईटीए-1 जीएएटी 1994 के अनुच्छेद II:1(बी) के अर्थ के दायरे में सीमा शुल्क ड्यूटियों और अन्य ड्यूटियों/ प्रभारों के विलोपन का अधिदेश देता है। चूंकि भारत ने आईटीए-1 पर हस्ताक्षर किए हैं, पीयूसी का आयात सीमा शुल्क ड्यूटी मुक्त है। अतः, आईटीए-1 आयातित पीयूसी के संबंध में भारत की "कार्रवाई की स्वतंत्रता"<sup>6</sup> को बाधित करता है और अन्य विश्व व्यापार संगठन संगत उपायों जैसे सीमा शुल्क ड्यूटियों को बढ़ाना, को करने से रोकता है। यह बताने योग्य है कि भारत का पूरी तरह मानना है कि जेएनएनएसएम के अधीन इसका डीसीआर जीएएटी 1994 के अनुच्छेद XX में वर्णित अपवादों के संगत है। परंतु, विश्व व्यापार संगठन अपीलीय बॉडी द्वारा 2016 में इस उपाय को खारिज करने के बाद, पीयूसी के लिए भारतीय बाजार सभी देशों से असीमित आयातों के लिए खुल गया। अतः, जीएएटी 1994 और आईटीए-1 के अधीन घरेलू उद्योग को तरजीह दिए बिना पीयूसी के असीमित टैरिफ मुक्त आयातों की अनुमति देने की भारत की बाध्यताओं के कारण भारत में पीयूसी की आयात मात्रा में महत्वपूर्ण और अनपेक्षित वृद्धि हुई है।

5.8.9 निष्कर्ष यह है कि पीओआई के दौरान पीयूसी के आयात में हुई औचक और तेज वृद्धि विभिन्न वैश्विक और घरेलू घटनाओं के सम्मिश्रण का परिणाम है, जो कि सभी अनपेक्षित और अप्रत्याशित थी। स्पष्टता के उद्देश्य से, ये अनपेक्षित और अप्रत्याशित गतिविधियां निम्नानुसार संक्षेप में पुनः बताई जा रही हैं:

(i) जब ईयू और यूएसए को निर्यात में बाधा आई तो, चीन की पीयूसी की विशाल उत्पादन और अतिरिक्त क्षमता जो कि अन्यथा निर्यातानुमुखी थी, को वैकल्पिक बाजार ढूंढना पड़ा, जो उन्होंने भारत में पाया;

(ii) ईयू और यूएसए में चीन से आयातित पीयूसी पर सुरक्षात्मक उपायों को लागू किए चीन के निर्यात का ध्यान भारत की ओर केंद्रित हो गया;

(iii) जेएनएनएसएम के अधीन यूएसए की भारत के डीसीआर को चुनौती के परिणाम से विश्व व्यापार संगठन विवाद समाधान बॉडी ने जीएएटी 1994 के अनुच्छेद III:4 तथा ट्रिप समझौते के अनुच्छेद 2.1 के अनुसार डीसीआर को असंगत करार दे दिया, जिसके कारण इसकी वापसी हुई तथा डीआई द्वारा गंवाए गए स्थान को भरे जाने के लिए आयात में परिणामी वृद्धि हुई।

(iv) 2015 के पेरिस समझौते पर भारत की प्रतिबद्धता ने पीयूसी के प्रयोग में वृद्धि की घरेलू प्रतिबद्धता की राह बनाई, जिसने ओर अन्य घटनाओं के साथ मिलकर आयात में वृद्धि की।

(v) पीयूसी के बढ़ते आयात की लैंड्रेड कीमत में गिरावट के साथ अन्य कारकों ने प्रतिस्पर्धात्मक समीकरण में बदलाव ला डीआई को हानि की स्थिति में ला दिया जो कि उनमें दिखाई भी दे रही है, अर्थात् डीआई आयात के सामने पीयूसी के घरेलू बाजार का हिस्सा खोती जा रही है; तथा

(vi) जीएएटी 1994 तथा आईटीए-1 के अधीन भारत की बाध्यताओं के कारण पीयूसी के आयात को भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ में निशुल्क कर दिया गया।

5.8.10 उपर्युक्त वर्णित विभिन्न वैश्विक तथा घरेलू अनपेक्षित तथा अप्रत्याशित स्थितियों के परिणामस्वरूप, भारत में पीयूसी के आयात में निर्विवाद रूप से सत्यापित वृद्धि हुई है। आयात में इस वृद्धि ने आयातित तथा घरेलू उत्पादित पीयूसी के प्रतिस्पर्धात्मक संबंध में ऐसा बड़ा बदलाव ला दिया जो डीआई के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। यद्यपि पीयूसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डीआई ने क्षमताएं स्थापित की है, पीओआई के दौरान बड़ी मात्रा में लगातार घटती लैंड्रेड कीमतों पर आयात में वृद्धि ने उत्पादन क्षमताओं को उपयोगहीन बना दिया तथा बिक्री में गिरावट दर्ज की गई।

## 5.9 गंभीर क्षति तथा/अथवा गंभीर क्षति की आशंका

5.9.1 निर्धारण किए जाने के लिए अगला मामला यह है कि क्या बड़ी मात्रा में पीयूसी के आयात में वृद्धि ने इसके समान अथवा सीधी प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई अथवा गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका पैदा हो रही है। अपनी विशेष प्रकृति के कारण यह बड़ी जटिल प्रक्रिया है क्योंकि पीयूसी के विषय में डीआई को गंभीर क्षति पहुंचने के लिए बहुत से मानदंड उत्तरदायी होते हैं जैसे घरेलू बाजार में इसका हिस्सा, आयात, बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपभोग आदि। इसके अतिरिक्त, यह भी महत्वपूर्ण है कि किसी मानदंड में हुई किसी एक नकारात्मक घटना को ही अंतिम न मान लिया जाए बल्कि देखा जाए कि ऐसा लगातार हुआ हो। तदनुसार बहुत से संगत मानदंड जिन्हें नीचे दर्शाया गया है की, यह निर्धारित किए जाने के लिए जांच की जा कि क्या पीओआई के दौरान पीयूसी के आयात में

<sup>6</sup> पैनेल रिपोर्ट, यूक्रेन - पैसंजर कार, पैरा 7.96.



वृद्धिने इसके समान अथवा सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है तथा/अथवा गंभीर क्षति पहुंचाने की आशंका है अथवा नहीं।

(i) घरेलू बाजार का हिस्सा: घरेलू मांग में तेजी से हो रहे विस्तार के पश्चात भी डीआई के बाजार हिस्से में गिरावट आई है; 2014-15 में डीआई का बाजार हिस्सा 13% था जो 2017-18 (ए) के दौरान गिरकर 7% रह गया। इसी अवधि के दौरान आयात का बाजार हिस्सा 86% से बढ़कर 90% हो गया।

बाजार हिस्सा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2017 तक)	2017-18 (वार्षिक)
आयात	1,275 (86%)	4,186 (94%)	6,375 (89%)	4,737 (90%)	9,474 (90%)
आवेदको/डीआई द्वारा घरेलू बिक्री	191 (13%)	276 (6%)	457 (6%)	358 (7%)	774 (7%)
अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा घरेलू बिक्री	9 (1%)	8 (0%)	325 (5%)	162 (3%)	325 (3%)
घरेलू उत्पादकों द्वारा कुल घरेलू बिक्री	200 (14%)	284 (6%)	782 (11%)	520 (10%)	1,099 (10%)
घरेलू मांग	1,476 (100%)	4,471 (100%)	7,157 (100%)	5,257 (100%)	10,573 (100%)

(ii) बिक्री: उक्त तालिका से यह पता चलता है कि घरेलू उत्पादकों की बिक्री 200 मेगावाट से बढ़कर 1,099 मेगावाट तक बढ़ गई। यद्यपि 899, यह ध्यान देने योग्य है कि जबकि घरेलू बिक्री गावाट तक बसे 899डी, आयात में 8, 199 तक वृद्धि हुई। अतः आयात में वृद्धि डीआई की बिक्री में वृद्धि के मुकाबले 9 गुना हो गई। साथ ही जबकि 2014-में घरेलू 15 मांग 1476 मेगावाट से बढ़कर 2017- 18(वार्षिकमें 10 (,मेगावाट हो गई 573, यह स्पष्ट है कि पीयूसी के बड़े आयात ने कथित उत्पादित उत्पादों की घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए घरेलू उत्पादन का स्थान ले लिया।

(iii) उत्पादन: 2014-15 में डीआई का उत्पादन 237 मेगावाट से बढ़कर 2017-18 (वार्षिक) में 838 मेगावाट हो गया। 2017-18 (वार्षिक) में ही डीआई की स्थापित क्षमता में 1,000 मेगावाट का बड़ा इजाफा हुआ। यद्यपि, 2017-18 में स्थापित क्षमता में इस वृद्धि के पश्चात भी उस वर्ष उत्पादन में केवल 365 मेगावाट की वृद्धि हुई। साथ ही, जबकि 2014-15 में पीयूसी आयात मात्रा 1275 मेगावाट से बढ़कर 2017-18 (वार्षिक) में 9474 मेगावाट हो गई अर्थात् 643% की वृद्धि, इसकी तुलना में डीआई का उत्पादन इसी अवधि के दौरान बढ़कर 254% हो गया। निम्नलिखित तालिकामें दिए गए आंकड़ों से यह निष्कर्ष स्पष्ट हो जाता है।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)	2017-18 (वार्षिक)
कुल आयात	मेगावाट	1,275	4,186	6,375	4,737	9,474
डीआई का उत्पादन	मेगावाट	237	295	473	381	838

(iv) क्षमता उपयोग : 2014-15 में डीआई की क्षमता उपयोग 60% से बढ़कर 2016-में 78 17% हो गया परंतु 2017- 18 (वार्षिक) के दौरान गिर कर 51% हो गया। आगे, 2017 - 18 (वार्षिकमें 1 में ही उत्पादन क्षमता (,मेगावाट की वृद्धि हुई 000, परंतु इस अतिरिक्त क्षमता का वस्तुतःकेवल 35 :% का ही उपयोग हो पाया, निम्नलिखित तालिका में यह दर्शाया गया है। वैसे भी, पीओआई की पूरी अवधि के दौरान डीआई की उत्पादन सुविधाओं का बड़े पैमाने पर कम उपयोग हुआ। पीयूसी के आयात के बढ़ते रुख के साथ क्षमता उपयोग के इस निम्न स्तर से डीआई को वर्तमान क्षति पहुंचने तथा और आसन्न क्षति की आशंका के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितं., 2017 तक)	2017-18 (वार्षिक)
स्थापित क्षमता	मेवा	392	573	604	727	1,653
डीआई का उत्पादन	मेवा	237	295	473	381	838
क्षमता उपयोग	%	60%	52%	78%	53%	51%

(v) रोजगार: क्षमता में बड़े इजाफे के बावजूद डीआई द्वारा रोजगार पैदा किए जाने में गिरावट दर्ज की गई। हाल ही में मई 2017

में एक आवेदक - मै. मुंद्रा सोलर पी वी लिमिटेड (एमएसपीवीएल) के प्रवेश ने पूरे तौर पर उद्योग में कुल कर्मियों की संख्या में समग्र रूप से वृद्धि दर्ज की गई है, परंतु यह उद्योग के रुख का परिचायक नहीं है। जबकी, यदि एम एस पीवीएल के कर्मियों की संख्या को हटा दिया जाए तो पूरे उद्योग में रोजगार की कमी दिखाई पड़ जाती है। आगे, जबकी घरेलू उद्योग पहले भी तथा अब भी स्थापित क्षमता [जैसा कि ऊपर (iv) में देखा गया] से कहीं निचले स्तर पर काम कर रहे हैं जिससे रोजगार संभावित अवसरों की बड़ी हानि हुई है।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितम्बर 2017 तक)
एमएसपीवीएल को छोड़कर कर्मियों की संख्या (अनुक्रमित)	100	135	128	127
वास्तविक कर्मियों की संख्या (अनुक्रमित)	100	135	128	460

- (vi) उत्पादकता: जैसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है जांच की पूरी अवधि के दौरान प्रत्येक कर्मी पर उत्पादन के रुख में गिरावट का रुख दिखाता है। यह दर्शाए जाने योग्य है कि मई 2017 में नए प्रवेशधारी एमएसपीवीएल के कारण हुई कर्मियों की संख्या में इजाफे के बावजूद भी इस अनुपात में उद्योग के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। 2014-15 में प्रत्येक कर्मी उत्पादन 0.316 मेगावाट था, जो 2015-16 में 0.291 मेगावाट हो गया। यद्यपि 2016-17 में यह मानदंड बढ़ कर 0.492 मेगावाट हो गया, 2017-18 में यह फिर से गिर कर केवल 0.243 मेगावाट के निम्न स्तर पर पहुंच गया। अतः उत्पादकता (प्रत्येक कर्मी पर उत्पादन) में वृद्धि तथा कमी होती रही तथा वर्तमान आंकड़े गिरावट का रुख दिखा रहे हैं और ऐसा कम से कम निकट भविष्य में भी जारी रह सकता है। यह स्पष्ट है कि डीआई उत्पादन बढ़ाने में अपनी स्थापित क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग किए जाने में असमर्थ रही।

(vii)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सित. 2017 तक)	2017-18 (वार्षिक)
डीआई का उत्पादन (मेगावाट)	237	295	472	381	838
कर्मियों की संख्या	749	1014	960	3445	3445
प्रति कर्मी उत्पादकता (मेगावाट)	0.316	0.291	0.492	0.221	0.243

- (viii) लाभ/हानि- पीओआई के दौरान डीआई को बड़ी भारी हानि हुई। 2016-17 की तुलना में 2017-18 (वार्षिक) के दौरान हानि दुगुनी से भी अधिक हो गई, अर्थात्- 155 इंडेक्स यूनिटों से 418 इंडेक्स यूनिट हो गयी। साथ ही घरेलू उद्योग को आधार वर्ष 2014-15 की तुलना में 2017-18 के दौरान हानि हुई। हानियों में ऐसी वृद्धि को क्षमता में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि तथा घरेलू बिक्री में वृद्धि जैसे तुलनात्मक मानदंडों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए। आगे शुद्ध बिक्री आंकड़ों में बड़ी गिरावट के कारण 2014-15 की तुलना में 2017-18 के दौरान (सितम्बर, 2017तक) हानियां बढ़ गई।

(ix)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सित. 2017 तक)	2017-18 (वार्षिक)
हानि रु लाख में (इन्डेक्स)	100	351	155	187	418
हानि रु बाट में (इन्डेक्स)	100	243	65	100	103

- (x) माल सूची: जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है पीओआई के दौरान डीआई की इवेंट्री बढ़ कर 4 गुना से भी अधिक हो गई।

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सित. 2017 तक)
अंतिम इवेंट्री (इन्डेक्स)	100	82	152	411

- (xi) प्राइस अंडरकटिंग: जैसा की नीचे दी गई तालिक से स्पष्ट है पूरी पीओआई के दौरान आयातित वस्तुओं की बड़े पैमाने पर प्राइस अंडरकटिंग देखी गई। यह स्पष्ट है कि उच्च स्तर की प्राइस अंडरकटिंग ने घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में वृद्धि करने से रोक दिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें हानि उठानी पड़ी।

विवरण	यूनिट	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सित. 2017 तक)	2017-18 (वार्षिक)
आयात की लैंडेड वैल्यू						
सौर सैल्स	रू./वाट	18.78	18.81	15.42	14.04	14.04
सौर मॉड्युल्स	रू./वाट	36.95	36.18	29.20	24.77	24.77
घरेलू उद्योग के शुद्ध विक्री आंकड़े						
सौर सैल्स (इन्डेक्स)	रू./वाट	100	94	88	62	62
सौर मॉड्युल्स (इन्डेक्स)	रू./वाट	100	103	82	92	92
प्राइस अंडरकटिंग						
सौर सैल्स (इन्डेक्स)	रू./वाट	100	83	100	37	37
सौर मॉड्युल्स (इन्डेक्स)	रू./वाट	100	173	121	458	458
प्राइस अंडरकटिंग %						
सौर सैल्स (इन्डेक्स)	%	100	83	122	49	49
सौर मॉड्युल्स (इन्डेक्स)	%	100	176	153	684	684

#### 5.10 वर्धित आयात और गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की आशंका के मध्य कारणीय संबंध-

5.10.1 कोरिया-डेयरी पर डब्ल्यू टी ओ पेनल ने “कॉजल लिंक” को निर्धारित करने हेतु बेसिक अप्रोच को निम्नानुसार स्थापित किया गया है:

“ इसके कॉजल लिंक निर्धारण में हमारी राय यह है कि राष्ट्रीय प्राधिकारियों को यह विश्लेषण एवं निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या उद्योग में हुई गतिविधियां, जिस पर राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा गंभीर क्षति को प्रदर्शित करने के लिए विचार किया गया, वर्धित आयात द्वारा गंभीर क्षति हो चुकी है। अपने कॉजल लिंक निर्धारण में, उस उद्योग कि स्थिति पर प्रभाव डालने वाले उद्देशीय एवं मात्रात्मक मात्र के सभी संगत तथ्यों के परीक्षण हेतु बाध्य है। इसके अलावा, राष्ट्रीय प्राधिकारियों ने वर्धित आयात के अलावा कुछ अन्य तथ्यों की पहचान की पहचान की है तो यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे तथ्यों द्वारा हुई क्षति को वर्धित आयात के कारण हुई क्षति के रूप में माना जाए। कॉजल लिंक स्थापित करने हेतु कोरिया को यह दिखाना होगा कि उसके घरेलू उद्योग को क्षति, वर्धित आयात के कारण हुई है। अन्य शब्दों में, कोरिया को यह दर्शाना कि एस एम पी पी के आयात से मिल्क पाउडर एवं कच्चा दूध बनाने वाले घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की स्थिति का आकलन करते हुये कोरिया प्राधिकारियों का कर्तव्य यह है कि अन्य कारकों से हुई क्षति को वर्धित आयात से आरोपित न करें।

5.10.2 2014-15 से 2017-18 (अप्रैल, 2017 तक) की अवधि के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पीयूसी का आयात काफी मात्रा में रहा है और पीयूसी के आयात मूल्य काफी नीचे आ गए हैं। इसके चलते घरेलू उद्योग ने अपने मूल्यों में संशोधन करते हुए उसमें

गिरावट की है। नतीजतन, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 5.9.1 (ix) के तहत तालिका में बताया गया है मूल वर्ष की तुलना में कुल बिक्री में कमी दर्ज की गई है।

**5.10.3** आयात द्वारा कम कीमत के परिणामस्वरूप घरेलू बिक्री मूल्यों में महत्वपूर्ण मूल्य अवसाद देखा गया है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है

विवरण (अनुक्रमित)	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2017 तक)	2017-18 वार्षिक)
बिक्री भाव	रुपए/वाट	100	87	78	81	84
भाव में मंदी (Y-o-Y)	रुपए/वाट		100	66	(-)22	(-)47
भाव में मंदी (संचयी)	रुपए/वाट		100	166	145	119
बिक्री की दर	रुपए/वाट	100	109	76	82	83
भाव में बढ़त (Y-o-Y)	रुपए/वाट		100	(-)353	61	78
मूल्य शमन (Y-o-Y)	रुपए/वाट		100	(-)124	16	10
मूल्य वृद्धि में रोकथाम	रुपए/वाट	100	243	65	88	79

**5.10.5** जांच की अवधि के दौरान और भविष्य में भी कुछ ऐसे निम्नलिखित प्रासंगिक कार्य कारण हैं जो वर्धित आयात और उसके द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण हो सकते हैं-

- पूर्ण रूप से 1275 मेगावाट से 9474 मेगावाट में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है;
- आयात की बाजार हिस्सेदारी 86% से बढ़कर 90% हो गई और परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्सेदारी में 13% से 7% की कमी आई है;
- चूँकि आयात, घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य की तुलना में कम मूल्य में उपलब्ध और साथ ही ओर घट रहा है, ग्राहक आयात उत्पाद की ओर रुख कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग न तो अपनी कीमतों को प्रमाणित कर पा रहे और साथ ही बढ़ती हुई माल सूची का सामना कर रहे हैं। कम कीमतों पर बढ़ते आयात का एक अन्य प्रभाव यह भी है कि भारत में विचारधीन उत्पाद की मांग / खपत में वृद्धि की दर की तुलना में घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने में असमर्थ हैं।
- कम कीमतों पर बढ़ते आयात का एक अन्य प्रभाव यह भी है कि भारत में विचारधीन उत्पाद की मांग/खपत में वृद्धि की दर की तुलना में घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने में असमर्थ हैं।
- हालांकि, पीयूसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा क्षमताएं स्थापित की गई हैं परंतु आयातित माल की लागत में लगातार गिरावट और काफी हद तक बढ़े हुए आयातों ने उत्पादन क्षमता को निष्क्रिय किया है और बिक्री में गिरावट को भी दर्ज किया है।
- घरेलू उद्योग बहुत भारी नुकसान उठा रहा है।

**5.10.6** संक्षेप में, ऊपर बताए गए मापदंडों का एक व्यापक मूल्यांकन दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंची है, और भविष्य में भी होने की वजह है और भविष्य में पीयूसी के बढ़ते हुए आयात के कारण क्षति होने की संभावना है। यह भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर, एक उद्देश्य और परिमाणगत प्रकृति के सभी प्रासंगिक कारकों को जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते हैं उनका मूल्यांकन किया गया है।

(घ) गंभीर परिस्थितियाँ

(6) कथित नियम के नियम 9 महानिदेशक रक्षोपाय को जाँच के संचालन और महत्वपूर्ण परिस्थितियों में शीघ्रता से आगे बढ़ने के लिए अधिकृत करता है। साथ ही गंभीर क्षति अथवा उसकी आशंका से संबन्धित प्रारम्भिक जाँच को रिकॉर्ड करने के अधिकार देता है। कथित नियमों के नियम 2(ब) द्वारा गंभीर परिस्थितियों को वह परिस्थितियाँ बताई गई हैं जहाँ स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हो रहा है कि वर्धित आयात के चलते घरेलू उत्पादक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और अनंतिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण न किये जाने से घरेलू उद्योग को आपूरणीय क्षति हो सकती है।

6.1 जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इतनी अधिक मात्रा में आयात किया गया है कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई। गंभीर परिस्थितियों कि विवेचना नीचे की गई है।

- (i) जाँच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयात का आयतन लगातार बढ़ा है और आयात की दरों में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त वर्ष की दूसरी छमाही में पी यू सी के आयात में हर वर्ष तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है जो कि 2016-17 की पहली छमाही से 2.7 पॉइंट अधिक है आयात के मूल्य में भी 2017-18 की पहली छमाही में 23.04 रुपए प्रति वाट की गिरावट आई है जो कि 23 प्रतिशत है। जैसे जैसे आयात की दरों में गिरावट आई घरेलू उद्योग की मुआवज़ा दर में भी गिरावट आई है। अंततः बिक्री और क्षमता प्रयोग पर भी इसका प्रतिकूल प्रयोग देखा गया।

वर्ष	आयात की मात्रा	आयात का मूल्य	आयात का भाव
2016-17	1720	5158	30.00
पहली छमाही 2016-17	4656	12375	26.58
दूसरी छमाही 2017-18 (पहली छमाही)	4737	11022	23.04

(ii) पी यू सी के बढ़ते हुए और निरंतर आयात के कारण, घरेलू उद्योग की कुल बिक्री में कमी आई है और तेजी में गिरावट आई है। बिक्री एवं क्षमता प्रयोग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(iii) मालसूची में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और प्रति व्यक्ति उत्पादकता में तीव्र गिरावट आई है।

(iv) घरेलू उद्योग को आयात दरों में गिरावट के कारण भारी नुकसान हो रहा है और जाँच की अवधि के दौरान मूल्य में सकारात्मक गिरावट दर्ज की गई।

**6.2** यह स्पष्ट है कि अंतिम रक्षोपाय उपाय के अधिरोपण में किसी भी प्रकार की देरी, डी आई को और क्षति पहुंचाएगी। मेरा निष्कर्ष है कि रक्षोपाय उपाय के तत्काल अधिरोपण हेतु विषम परिस्थितियाँ विद्यमान हैं।

(ङ) प्रारंभिक जाँच

(7) सम उप करने के लिए, जाँच की अवधि के दौरान डी आई की फंक्शनिंग में सम्पूर्ण कमी थी। इससे भी ज्यादा, अपकर्ष मानदंडों की प्रवृत्ति, क्षति की गंभीर आशंका का सूचक है जो आगामी दिनों में जारी रह सकती है। पीयूसी के वर्धित आयात के कारण डी आई को हुई गंभीर क्षति के मानदंडानुसार निष्कर्ष को निम्नानुसार संक्षेप में दिया गया है।

(क) पीयूसी के आयात की मात्रा बढ़ी है एवम् वास्तविक एवं संबंधी, दोनों मर्दों में बढ़ रही है।

(ख) डी आई का मार्केट शेयर घटा है, जबकि आयात का मार्केट शेयर बढ़ा है।

(ग) पीयूसी के वर्धित आयात ने डी आई की बिक्री को विकल्प दिया है।

(घ) पीयूसी के डी आई का उत्पादन बढ़ा है, क्षमता उपयोग काफी कम रहा है।

(ङ) पीयूसी हेतु घरेलू मांग में वृद्धि के बावजूद क्षमता उपयोग काफी कम रहा है।

(च) क्षमता रोजगार अवसर में पर्याप्त कमी का सामना डी आई ने किया है।

(छ) प्रति कर्मचारी उत्पादकता में कमी की प्रवर्ती देखी गई है।

(ज) डी आई को महत्वपूर्ण हानि हो चुकी है।

(झ) पीयूसी के क्लोजिंग ईवेंट्स बढ़ी है, एवं

(ञ) जांच की अवधि के दौरान आयातित पीयूसी द्वारा मूल्यों में कमी, सकारात्मक है।

7.1 यहाँ यह नोट करना संगत है कि डी आई को लगातार गंभीर क्षति उठानी पड़ी है एवं आगे भी वे गंभीर क्षति की आशंका का सामना कर रहे हैं। आयात वाल्यूम्स में प्रवर्ति, मजबूती से यह दर्शाती है कि चीन में अधिक क्षमता के कारण, चीन में उत्पादकों के निर्यात उन्मुक्त होने एवं यूएसए एवं ई यू जैसे अन्य महत्वपूर्ण बाजारों में चीन उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा छोड़े गए मौकों के कारण, भविष्य में पीयूसी के आयात में वृद्धि की संभावना है जो ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों को भारत को टारगेट करने को विवश करेगी। क्योंकि आयातित वस्तुओं ने भारतीय घरेलू उद्योग के मूल्यों को महत्वपूर्ण डिग्री तक कम कर दिया है तो अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से मिलान हेतु, पुनर्गठन हेतु समय की आवश्यकता होगी। अन्यथा उन्हें आगे भी क्षति होगी। अतः गंभीर क्षति की आशंका भी आसन्न पाई गई है।

7.2 उपरोक्त की दृष्टि में, मेरा प्रारम्भिक निष्कर्ष यह है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति एवं आयातों में वृद्धि में सीधा संबंध है। जाहिर है कि निष्कर्ष को लीड करने हेतु सभी सूचक विद्यमान है कि वर्धित आयात, जिसमें कमी का कोई संकेत नहीं है एवं इसके विपरीत इसमें वृद्धि हो रही है एवं आने वाले दिनों में डी आई को क्षति पहुँचने की आशंका है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की आशंका से बचाने की दृष्टि से अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपन की तत्काल आवश्यकता है। यदि रक्षोपाय उपाय लगाने में देरी की गई तो सुधार मुश्किल होगा। वास्तव में, दस्तावेजों एवं रिकार्ड पर सूचना के आधार पर ये प्रारम्भिक निष्कर्ष है एवं कोई अन्य तथ्य, जो मेटेरियल असर रखता है, जांच के दौरान सामने आता है तो आगामी दिनों में इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

#### (च) विकासशील देश

(8) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ख (1) के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि विकासशील देश से आने वाले समान पर जब तक रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाएगा जब तक उस वस्तु के कुल आयात का 3% से अधिक इसका आयात पार नहीं हो जाता। यदि समान एक से अधिक देशों से आयात हो रहा है तो उस वस्तु के कुल आयात का 9% से अधिक नहीं बढ़ता हो। आगे, अधिसूचना संख्या 19/2016-सीमा शुल्क(एन टी) दिनांक 5 फरवरी 2016, इन प्रावधान के प्रयोजनों हेतु विकासशील देशों को स्पष्ट करते हैं। वर्तमान मामले में, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कथित अधिसूचना के साथ पठित इस विधिक प्रावधान को लागू करने पर निष्कर्ष यह है कि पीयूसी का आयात एक से अधिक विशिष्ट विकासशील देशों से हो रहा है जिसमें चीन पी आर एवं मलेशिया शामिल है। तथापि, भारत में पीयूसी के कुल आयात के प्रतिशत के रूप में, चीन पी आर एवं मलेशिया से आयात 3% से अधिक है जबकि प्रत्येक अन्य विकासशील देश का व्यक्तिगत रूप से 3% से कम है। विकासशील देशों, जिनका व्यक्तिगत शेयर 3% से कम है ये भारत में पीयूसी के कुल आयात के 9% से अधिक नहीं है। अतः यह मानना चाहिए कि सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8 ख (1) के प्रावधानों के अनुसार विकासशील देशों (चीन पीआर एवं मलेशिया के अलावा) से आने वाले पीयूसी के आयात पर रक्षोपाय शुल्क एटरेक्ट नहीं होगा।

#### (छ) रक्षोपाय उपायों का कार्यक्षेत्र

(9) जैसा कि ऊपर वर्णन है, आवेदकों में एस ई जेड शामिल है, एवं वे भी डी आई के रूप में माने जाने को क्वालिफाई करते हैं। एस ई जेड यूनिट, एस ई जेड अधिनियम 2005 एवं उसकी धारा 30 से शासित होती है, जिसमें प्रावधान है कि घरेलू बाजार में एसईजेड द्वारा निकासी की गई वस्तुओं पर भुगतान योग्य शुल्क वैसी ही होगी जैसा कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन, देश में, कथित वस्तुओं के आयात पर उद्धृत की जाती है।

इस प्रकार, वर्तमान मामलों में, यदि घरेलू बाजार हेतु एक एस ई जेड द्वारा निकासी की गई थी तो कोई भी रक्षोपाय शुल्क, जो कि देश में पीयूसी के सीधे आयात लगाई जाती है तो यह ऐसी निकासी पर भी एट्रेक्ट होगी / इसका प्रभाव है कि डी आई का एक हिस्सा, जो एस ई जेड में आपरेट करता है, न केवल रक्षोपाय उपाय की सुरक्षा को खोदेगा बल्कि मुद्दों की और बुरा बनादेगा, वे कथित उपाय/ उद्धरण के स्वयं अध्यधीन होंगे।

दूसरे शब्दों में, एस ई जेड 2005 की धारा 30 को लागू करना, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ख के अधीन रक्षोपाय उपायों के अधिरोपण को बेकार बना देगा एवं विपरीत होगा। इसके लिए उपाय यह हो सकता है कि जब एस ई जेड यूनिट से घरेलू बाजार हेतु पी यू सी की निकासी की जाती है, तब रक्षोपाय उपाय के हद तक झूटी छूट हो। यह डी आई के हितों में

रक्षोपाय उपायों की साथकता को बरकरार रखेगा। इससे सभी घरेलू उत्पादकों अथवा डी आई के सभी घटकों को रक्षोपाय उपायों की व्यवहार्यता के संबंध में एक समान रखने पर समानता के केनन को संतुष्ट करेगा। तथापि, यह मामला इस कारवाही की एम्बिट से बाहर आता है जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के साथ पठित इसके नियमों के प्रावधानों द्वारा सख्ती से शासित होता है एवं इसलिए, सरकार के विचार हेतु छोड़ दिया गया है। आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिधीन यदि कोई सामान एस ई जेड से घरेलू बाजार में निकाला जाता है या किसी वस्तु के निर्माण, जो कि घरेलू टैरिफ में एस ई जेड से निकासी की जाती है, में प्रयुक्त की जाती है तो रक्षोपाय शुल्क के उद्घाटन से डील करने वाले सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8 ख(2ए) (II) के प्रावधान लागू होंगे।

(ज) संस्तुतियां

10 उपरोक्त विश्लेषण एवं निष्कर्ष की दृष्टि में, मेरा निष्कर्ष है कि विचारधीन उत्पाद अर्थात् “सोलर सेल्स, भले माड्यूल या पेनल में असेम्बलड हो न हो” का भारत में इतनी वर्धित मात्रा में एवं ऐसी परिस्थितियों के आधीन आयात हो रहा कि यह उसके जैसे या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पाद बनाने वाले डी आई को क्षति की आशंका है या गंभीर क्षति पहुंचा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि गंभीर क्षति से घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए वर्तमान विषम परिस्थितियाँ, अंतिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण को न्यायोचित ठहराती हैं। यदि संस्तुत रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने में देरी की गई तो घरेलू उद्योग की सुधार मुश्किल होगी। तदनुसार मैं, निम्नलिखित संस्तुति करता हूँ:-

(i) अंतिम निर्णय के लंबित रहने तक, सोलर सेल्स एवं माड्यूल के आयात मात्रा अनुपात के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी की बिक्री की औसत लागत, ब्याज के अलावा बिक्री की लागत पर पर्याप्त रिटर्न, आयात ड्यूटी के वर्तमान स्तर एवं पीयूसी की वर्तमान औसत आयात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, खंड (III) में दर्शाए गए विकासशील देश के अलावा सभी देशों से होने वाले “सोलर सेल्स, भले माड्यूल या पेनल्स में असेम्बलड हो या न हों” पीयूसी के आयात पर 70% (सत्तर प्रतिशत) यथामूल्य की दर से अंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाए। यहाँ वर्णित टैरिफ आइटम केवल सूचक है एक आयातित वस्तुओं का विवरण, संस्तुत रक्षोपाय शुल्क की प्रयोज्यता को निर्धारित करेगा।

(ii) मैं यह भी संस्तुत करता हूँ कि कथित उत्पाद के आयात पर रक्षोपाय शुल्क, उपरोक्तनुसार, 200 दिनों (दो सौ दिनों) की अवधि के लिए लगाया जाए जो कि घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु न्यूनतम अवधि समझी गई है।

(iii) क्योंकि अधिसूचना संख्या 19/2016- सीमा शुल्क (एन टी) दिनांक 05 फरवरी 2016 में सूचीबद्ध विकासशील देशों, चीन पी आर एवं मलेशिया के अलावा, से आयात प्रत्येक का 3% से अधिक नहीं है एवं समग्र रूप से 9% से अधिक नहीं है अतः ऐसे विकासशील देशों, चीन पीआर एवं मलेशिया के अलावा “सोलर सेल्स भले ही माड्यूल या पेनल्स में असेम्बलड हों या ना हो” से आयात पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा ख (I) के प्रावधानों के अनुसार, अंतिम रक्षोपाय शुल्क एटरेक्ट नहीं होगा।

(ट) आगे की कार्रवाई

11. विभिन्न पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, जहाँ आवश्यक हों सत्यापन के आधीन होगी जिसके लिए उन्हें अलग से सूचित किया जाएगा। यह प्रारम्भिक निष्कर्ष, डी आई द्वारा प्रस्तुत किए आंकड़ों के आधार पर निकाला गया है एवं प्राधिकारियों द्वारा आगामी जांच के आधीन होगा।

11.1 अंतिम निर्णय करने से पूर्व एक सार्वजनिक सुनवाई की जाएगी जिसके लिए तारीख अलग से सूचित की जाएगी।

[फा. सं. 22011/68/2017]

संदीप एम. भटनागर, महानिदेशक

**MINISTRY OF FINANCE**  
(DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS)  
(CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, 5th January 2018

**Subject: Safeguard investigation concerning imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” into India – Preliminary Findings - Proceedings under the Customs Tariff Act, 1975 and the Custom Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 - Reg.**

**G.S.R. 16(E).— (A) Introduction**

1. An application dated 28.11.2017 has been filed before me on 05.12.2017 under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 (hereinafter also referred to as the “said Rules”) by the Indian Solar Manufacturers Association (ISMA) on behalf of five Indian producers, namely (i) M/s Mundra Solar PV Limited, Adani House, Meetha Khali 6 Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat; (ii) M/s Indosolar Limited, 3C/1, EcoTech-II, Udyog Vihar, Dist: Gautam Budh Nagar, Greater Noida-201306, Uttar Pradesh; (iii) M/s Jupiter Solar Power Limited, Village Katha, Post Office Baddi, Teh. Nalagarh, Dist. Solan, Himachal Pradesh-173205; (iv) M/s Websol Energy Systems Limited, Falta SEZ Sector-II, Falta, Dist: 24 South Praganas, West Bengal-743504; and (v) M/s Helios Photo Voltaic Limited, 43B, Okhla Industrial Estate, Phase-III, New Delhi-110020, through M/s Athena Law Associates, 808, L&T Building, Sector 18B, Dwarka, New Delhi-110075, seeking imposition of Safeguard Duty on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC”) into India to protect the Domestic Industry of like or, directly competitive products from serious injury / threat of serious injury caused by their increased imports. The applicants have claimed that on account of the surge in imports of the PUC many domestic producers have kept their production facilities almost idle and the heavy losses have crippled the Domestic Industry. For this reason, the applicants have also requested for imposition of provisional Safeguard Duty as a measure to mitigate their injury.

**(B) Procedure Followed**

2. An examination of the application and the evidence / details / documents submitted therewith led to the conclusion that the application satisfies the requirements of Rule 5 of the said Rules. Therefore, a Safeguard investigation against imports of the PUC into India was initiated vide Notice of Initiation (NOI) dated 19.12.2017. The NOI was published in the Gazette of India, Extraordinary dated 19.12.2017 vide GSR No.1522 (E).
3. In accordance with sub-rules (2) and (3) of Rule 6 of the said Rules, a copy of the NOI dated 19.12.2017 and a copy of a Non-confidential Version (NCV) of the application dated 28.11.2017 filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Finance and Ministry of New and Renewable Energy, the Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the interested parties mentioned in the said application. Further, the questionnaire to be answered by the exporters / importers / domestic producers, as prescribed under Rule 6(4) of the said Rules, was forwarded to the known interested parties with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the NOI.
4. On 20.12.2017, the two associations of the domestic Solar Cells producers, namely (i) M/s Indian Solar Manufacturers Association (ISMA) and (ii) M/s Solar Power Developers Association (SPDA) were sent a copy of the NOI dated 19.12.2017, a copy of the NCV of the application dated 28.11.2017 and the questionnaire to be answered by the exporters / importers / domestic producers.

**(C) Observations**

5. I have carefully examined the said application and the duly certified financial and other records produced by the applicants. My preliminary observations on various factors that are relevant to the present proceedings of investigating imposition of a Safeguard Duty on imports of “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” into India to protect the Domestic Industry of like and directly competitive products against serious injury / threat of serious injury caused by their increased imports are as follows:

**5.1 The Product Under Consideration (PUC)**

5.1.1 The PUC is “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” classifiable under Tariff Heading 8541 and Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975. Solar Cells are also known as Photovoltaic Cells in the market parlance. Photovoltaic technology enables direct conversion of sunlight into electricity at the atomic level and Solar Cells are solid state electrical devices that convert sunlight directly into electricity by the photovoltaic effect. For practical use, Solar Cells are packaged and connected into an assembly and such an assembly of Solar Cells is referred to as a Solar Panel or Solar Module. The electrical connections are made to the Solar Cells in series to achieve desired output wattage and / or in parallel to provide a desired current capability.



5.1.2 The PUC is being manufactured using either of the two major technologies: (1) Crystalline Silicon (c-Si) based Solar Cell technology, also known as Silicon Wafer based technology, and (2) Thin Film technology. The c-Si technology may use n-type and p-type Silicon, and also mono crystalline and multi crystalline Silicon materials. The Thin Film technology may use Amorphous Silicon, Cadmium Tellurium (CdTe) or Copper Indium Gallium Selenum as semi-conductor materials. Solar Cells based on both c-Si technology and Thin Film technology are imported into India.

5.1.3 The applicants manufacture Solar Cells / modules / panels using only c-Si technology and not Thin Film technology. The applicants have claimed that Solar Cells based on both c-Si and Thin Film technologies are used in Solar power plants. According to the applicants, the Central Government projects such as Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM) or projects of various State Governments neither differentiate the technologies nor award separate auction price for projects based on different technologies. Moreover, there are no material differences between Solar Cells based on either of these technologies and these are all meant for the same end uses. Therefore, the applicants contend that the domestically produced PUC based on c-Si technology are like and directly competitive products to the imported PUC based on either c-Si technology or Thin Film technology.

## 5.2 Domestic Industry (DI)

5.2.1 Clause (b) of sub-section (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 defines Domestic Industry (hereinafter also referred to as the "DI"), as follows:

‘(b) “Domestic industry” means the producers -

- i. as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
- ii. whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.’

5.2.2 The applicants have claimed that their collective production accounts for more than 50% of the total production of the PUC in India, as indicated in the table below. The applicants contend that by virtue of this fact, they represent a major proportion of the total Indian or domestic industry of the PUC and therefore, they have the standing to file the present application and be treated as the Domestic Industry.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Total Indian production	MW	246	305	798	544	1,164
Production of the DI (applicants)	MW	237	295	473	381	838
Share of production of the DI in total Indian production	%	96	97	59	70	72

5.2.3 After taking into account the information on record, it is determined that the production of the applicants constitutes a major share of the total production of the said products in India. Accordingly, the applicants constitute the Domestic Industry or the DI in terms of clause (b) of sub-section (6) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975.

5.2.4 In the context of determining the applicants as the DI, it is noted that three of the applicants, namely M/s Mundra Solar PV Limited, M/s Websol Energy Systems Limited and M/s Helios Photo Voltaic Limited are based in Special Economic Zones (SEZ). The SEZ scheme is an export promotion scheme of the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. This scheme extends certain fiscal and non-fiscal benefits to the units operating thereunder with a view to encourage exports. In this direction, by creating a legal fiction, the SEZ units are treated as if these are outside India. However, the SEZ units are physically very much in India and in like manner of other domestic manufacturing units, these units adhere to domestic laws (though at times with some relaxations), generate employment, make domestic sales etc. Thus, increase in imports of any item also impacts SEZ units in like manner as it does any other domestic producer operating outside the SEZs. Therefore, the applicant SEZ units qualify as part of the DI (indeed, by virtue of the quantum of production of the applicants, as the DI itself). All other SEZ units that are similarly engaged in production of like or directly competitive products would also be treated as a part of the DI.

## 5.3 Period of Investigation (POI)

5.3.1 The Customs Tariff Act, 1975 and the said Rules as well as the WTO Agreement on Safeguards and Article XIX of GATT neither define nor provide guidance regarding the period of investigation. However, it is evident that the investigation period should be adequately long and sufficiently recent in time to allow reasonable conclusions to be drawn on the basis of various relevant factors such as domestic market conditions, performance of DI etc., as to whether or not the increased imports are indeed causing serious injury or threatening to cause serious injury to the DI and therefore justify the need for imposition of Safeguard Duty. On this basis, in the present case, it is considered reasonable and just to determine the period of investigation (POI) as 2014-15 to 2017-18 (Annualized).

#### 5.4 Source of Information

5.4.1 The DI have submitted transaction-wise import data for the PUC, which has been sourced from: (i) Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), Department of Commerce, Government of India for the period from 2014-15 till the end of First Quarter of 2017-18; and (ii) M/s Infodrive India, New Delhi for the period of the second quarter (July, 2017 to September, 2017) of 2017-18. The corresponding data for the period 2014-15 to 2017-18 (upto September, 2017) in respect of the DI itself has been submitted by the applicants and the same has been verified on the basis of their (i) cost audit reports; (ii) financial records; (iii) various other records pertaining to production, sales, inventory etc. In addition, the import data for the period July, 2017 to September, 2017 have been separately obtained from DGCI&S, Ministry of Commerce, Kolkata. All this data has been taken into consideration for analysis.

#### 5.5 Confidentiality of Information Submitted

5.5.1 The DI have provided some information in their application on confidential basis and has requested that it be treated as confidential. The DI have also provided a non-confidential version (NCV) of their application, as required under Rule 7 of the said Rules read with Trade Notice dated 21.12.2009 issued by Director General (Safeguards) under File No. D-22011/75/2009. Further, the DI have submitted reasons justifying their claim of confidentiality of this information.

5.5.2 In terms of Rule 7 of the said Rules, the applicant may choose not to disclose information which is by nature confidential and provide a non-confidential summary thereof. The DI have submitted reasons for claiming confidentiality of the information and furnished a non-confidential summary of the information filed on confidential basis. Upon a careful examination of the reasons advanced by the DI, I find that these reasons satisfy the requirements of Rule 7 of the said Rules. Accordingly, the confidentiality claimed by the applicants is hereby granted.

#### 5.6 Increasing Imports in Absolute Terms

5.6.1 The PUC is being imported into India from various countries including China PR, Malaysia, Singapore and Taiwan. The major quantity of the PUC is being imported from China PR. As seen, the import volumes of the PUC have increased from 1,275 MW in 2014-15 to 9,474 MW in 2017-18 (Annualized). This is an increase of 643% in 2017-18 (Annualized) from the base year 2014-15. Thus, there is no doubt that the import volumes have increased significantly each year. Moreover, there has been a sudden surge in imports volumes during the first six months of 2017-18 which is 74% of the imports in 2016-17. The increasing import volumes of the PUC both in absolute terms and per cent. terms during the period 2014-15 to 2017-18 (Annualized) is indicated in the table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Total imports	MW	1,275	4,186	6,375	4,737	9,474
% increase in imports over previous year	%	-	228	52	-	49

#### 5.7 Increasing Imports in Relative Terms

5.7.1 Relative to domestic production, imports of the PUC are found to have consistently increased between 2014-15 and 2017-18 (Annualized). The growth rate of such imports as a percentage of the domestic production was a remarkable 1,371% during the intervening year 2015-16. Even the overall growth rate of the imports of the PUC relative to its domestic production is very significant, rising from 519% in 2014-15 to 814% in 2017-18. Thus, during the entire POI, the import volumes of the PUC relative to its domestic production have consistently increased significantly, as indicated in the table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Total imports	MW	1,275	4,186	6,375	4,737	9,474
Indian production	MW	246	305	798	544	1,164
Imports as a % of Indian production	%	519	1,371	799	871	814

#### 5.8 Unforeseen Developments

5.8.1 Neither Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 nor the Rules made thereunder impose an obligation on the Director General (Safeguards) to analyze the unforeseen developments as a result of which the increased imports have occurred. The legal provisions neither contain any parameters that must be verified to

identify the unforeseen developments nor do they specify any methodology that must be followed in the analysis of such unforeseen developments. However, the WTO Agreement on Safeguards read with Article XIX of GATT obligates the national authorities to examine “unforeseen developments” that led to the increase in imports and the consequent serious injury to the DI. In view of this requirement, this Directorate has consistently been examining the issue of “unforeseen developments” in its investigations. Therefore, even in the present case, it is considered appropriate to examine the unforeseen developments or circumstances that have led to the sharp increase in the imports of the PUC during the period of investigation. However, in order to do so, it is necessary to first appreciate the import of the term “unforeseen developments or circumstances” and for this, a reference needs to be made to various rulings of the Appellate Body of WTO.

5.8.2 The Appellate Body of WTO in *Argentina–Footwear (EC)*<sup>1</sup> case held that imports in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers, must have been ‘unexpected’. In that case it was also held that the development of increased imports must have been due to “unforeseen developments”. Similarly, the Appellate Body of WTO in *Korea–Dairy*<sup>2</sup> case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when member incurred that obligation. In that case it was also recognized that unforeseen developments are *circumstances* which must be demonstrated as a matter of fact. In another case, the Panel on *US–Steel Safeguards*<sup>3</sup> concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development. It was also noted that increased imports must be an outcome of unforeseen developments i.e., it is the unforeseen developments that resulted in increased imports.

5.8.3 Applying the aforementioned findings to the present case, it is clear that the temporal nature of the increase in imports of the PUC so as to cause serious injury to the DI or give rise to a threat of such serious injury must have been unforeseen or unexpected and factual. Whereas the event of increased imports itself must be demonstrable on the basis of data on imports, a finding on its unforeseen or unexpected nature must be contextual. In the present case, a relevant context for this would be the event or events that resulted in tariff concessions on the import of the PUC into India. In other words, the factum of increased imports of the PUC during the POI must have been unforeseen at the time of incurring the obligations i.e., accession to WTO, resolving to abide by the commitments under various WTO Agreements, providing tariff concessions and subsequently amending those tariff concessions through the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products (ITA-I) on 13<sup>th</sup> December, 1996.

5.8.4 In the context of determining if the present development of a significant and sharp increase in imports of the PUC during the POI was indeed an unforeseen or unexpected development, the evidence furnished by the applicants has been examined and the findings thereon are, as follows:

- (i) China<sup>4</sup> has more than doubled its production capacity of Solar Cells from 11.12 GW in 2012 to 27.78 GW in 2016. Similarly, the production capacity of Solar Modules increased from 12.46 GW in 2012 to 35.47 GW in 2016. Further, data of 35 producers who collectively account for 57% of Solar Cells and 67% of Solar Modules production in China reveals excess capacity, as indicated in the table below. This aspect of having a huge production base coupled with excess capacity have a bearing on the applicants' case that there has been a surge in imports of the PUC from China.

Solar Cells					
In GW	2012	2013	2014	2015	2016
Capacity (Cells)	16.70	19.30	22.19	26.46	33.13
Production (Cells)	11.12	14.03	18.54	22.72	27.78
Domestic consumption	10.68	13.06	17.31	22.26	26.76
Exports	0.40	0.81	0.87	0.52	0.50
Idle capacity	33.41%	27.31%	16.49%	14.13%	16.15%
Solar Modules					
Capacity (Solar Modules)	20.13	22.77	27.99	34.71	46.40
Production (Solar Modules)	12.46	16.32	22.07	28.79	35.47

<sup>1</sup> Appellate Body Report, *Argentina – Footwear (EC)*, para. 91  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds121\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds121_e.htm);

<sup>2</sup> Appellate Body Reports, *Korea – Dairy*, para. 85 and 89  
[\[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds98\\_e.htm\]](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds98_e.htm).

<sup>3</sup> Appellate Body Report, *US – Steel Safeguards*, para. 315  
[\[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/248\\_259\\_abr\\_e.pdf\]](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/248_259_abr_e.pdf).

<sup>4</sup> Findings of the United States International Trade Commission [USITC] in Section 201 proceedings against Crystalline Silicon Photovoltaic Cells (Whether or not Partially or Fully Assembled into Other Products) - Publication No. 4739  
[\[https://www.usitc.gov/trade\\_remedy/731\\_ad\\_701\\_cvd/investigations/pub4739-vol\\_i\\_and\\_vol\\_ii\\_0.pdf\]](https://www.usitc.gov/trade_remedy/731_ad_701_cvd/investigations/pub4739-vol_i_and_vol_ii_0.pdf)

Domestic consumption	2.46	5.94	7.73	12.86	20.69
Exports	9.61	10.39	13.64	15.62	13.93
Idle capacity	38.10%	28.32%	21.15%	17.05%	23.99%
Exports share in production	77.12%	63.66%	61.80%	54.25%	39.27%

- (ii) China's export orientation in respect of the PUC is unquestionable, but a material fact that emerges is that during the past two years, both its direction and volume of export trade changed in a significant manner *towards* India, as is established from the table below. To illustrate, while China's exports to India constituted a paltry 1.52% of its total global exports during 2012, this increased to 21.58% during 2016.

Chinese Exports To (USD 000') <sup>5</sup>	2012	2013	2014	2015	2016
World	12,775,263	10,150,759	12,319,183	12,938,427	11,347,462
Japan	892,923	2,794,236	4,394,922	3,341,833	2,558,724
India	193,756	510,278	488,619	1,356,754	2,448,216
USA	1,416,963	1,208,074	1,818,175	1,634,799	1,368,664
EU	8,283,128	2,914,197	2,352,842	2,054,177	1,288,605
Share of India	1.52%	5.03%	3.97%	10.49%	21.58%
Share of EU + USA	75.93%	40.61%	33.86%	28.51%	23.42%

- (iii) The aforementioned shift in direction of Chinese exports of the PUC to India gets re-confirmed from the data of more current times. As indicated in the table below, during the first half of 2016 (H1 2016) Chinese exports to India were 18.51% of its total exports, as compared to which its combined exports to EU and USA were 30.65% (of its total exports). The situation turned dramatically during the succeeding two half yearly periods. In the second half of 2016 (H2 2016), China's exports to India constituted 25.09% while its exports to EU & USA fell to 15.12%. Again, in the first half of 2017 (H1 2017), China's exports to India increased to a staggering 38.77% of its total exports while its exports to EU and USA shrunk to just 5% (of its total exports). Such a significant shift in pattern of trade in which China started targeting the Indian market more vigorously as compared to developed countries / markets like EU and USA etc. could not have been foreseen.

Chinese Exports To (USD 000') <sup>6</sup>	H1 2016	H2 2016	H1 2017
World	6,062,679	5,284,783	5,350,966
India	1,122,083	1,326,133	2,074,573
Japan	1,219,493	1,339,231	1,095,773
EU	838,606	450,002	233,481
USA	1,019,870	348,793	34,268
Share of India	18.51%	25.09%	38.77%
Share of EU + USA	30.65%	15.12%	5.00%

5.8.5 Another unforeseen development that contributed in the surge in imports of the PUC in India and a shift away from other foreign markets was the imposition of trade remedy measures by the EU and USA on imports from China. The Anti-dumping and Countervailing duty orders in the USA associated with (i) the Crystalline Silicon Photovoltaic (CSPV 1) investigations became effective on 07.12.2012 and (ii) the CSPV 2 investigations became effective on 18.02.2015. Also, in the EU, the provisional measure came into effect on 05.06.2013 [Commission Regulation (EU) No. 513/2013 of 04.06.2013] and the final measure was imposed on 05.12.2013 [Commission Regulation (EU) No. 1238/2013 of 02.12.2013]. The immediate impact of these measures was not visible in India because of the requirement of Domestic Content Requirements (DCR) under the Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JNNSM). Thus, the DI had the assurance of a captive domestic market to the extent dictated by the DCR. However, in 2013, the USA challenged the DCR under JNNSM before the WTO Dispute Settlement Body and the outcome was that in October 2016,

<sup>5</sup> www.trademap.org

<sup>6</sup> www.trademap.org

the WTO Appellate Body held the DCR to be inconsistent with Article III:4 of the GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement. Hence, India withdrew the DCR. Pursuant to the withdrawal of DCR, the changes in the pattern of trade became more pronounced with imports of the PUC increasing substantially. As afore stated, these developments could not have been foreseen.

5.8.6 In 2015, India committed to the Paris Agreement on climate change for reduction of CO<sub>2</sub> emissions by 33-35% from 2005 levels, to address global warming. In line with this commitment, India established a target of achieving 100 GW of Solar power generation by the year 2022. This commitment pushed up the demand for Solar power generation projects in India. It is clear that the commitment given by India under the Paris Agreement that was signed by 197 countries (as on date ratified by 172 countries) was unforeseen at the time the import tariff concession for the PUC was agreed to under ITA-1 on 13<sup>th</sup> December, 1996. Similarly, the huge increase in the demand for the PUC in India in a short period of time which has in part fuelled the surge in imports was also unforeseen.

5.8.7 Another relevant factor that has emerged is that the imports of the PUC are taking place at very low prices; there has been a sudden and appreciable drop in the landed value of the imported PUC, as evident from the table below. The immediate impact of this has been that the Domestic Industry faced a drop in sales realisation of their products. Thus, the surge in imports at consistently falling landed price changed the competitive relationship between imports and domestic production, to the disadvantage of the latter. This has hampered the DI's ability to compete and make and sell the PUC. It is but evident that this change in the competitive relationship was entirely unforeseen.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
<b>Landed value of imports</b>						
Solar Cells	Rs./Watt	18.78	18.81	15.42	14.04	14.04
Solar Modules	Rs./Watt	36.95	36.18	29.20	24.77	24.77
<b>Net sales realisation of Domestic Industry</b>						
Solar Cells (Indexed)	Rs./Watt	100	94	88	62	62
Solar Modules (Indexed)	Rs./Watt	100	103	82	92	92

5.8.8 India's import tariff on the PUC falling under Customs Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975 is 'Free'. This 'Free' tariff was introduced pursuant to the obligations on India under GATT 1994, including the tariff concessions thereunder read with the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products dated 13th December, 1996 (hereinafter also referred to as the "ITA-1"). The PUC is covered under Attachment A, Section 1 of the ITA-1. The ITA-1 mandated elimination of Customs duties and other duties / charges of any kind within the meaning of Article II:1(b) of GATT 1994 on the products listed therein. Since India is a signatory to ITA-1, the imports of PUC are free of Customs duties. Thus, ITA-1 binds India's "freedom of action"<sup>7</sup> with respect to the imported PUC and prevents it from taking other WTO-consistent measures, such as increasing the Customs duties. It merits mention that India truly believed that its DCR under JNNSM was consistent with the exceptions contained in Article XX of GATT 1994, but after the rejection of this measure by the WTO Appellate Body in 2016, the Indian market for the PUC became open for unrestricted imports from all countries. Thus, India's obligation under GATT 1994 and ITA-1 to allow unrestricted tariff free imports of the PUC without giving preference to domestic production has led to a significant and unforeseen increase in the import volumes of the PUC into India.

5.8.9 The conclusion is that the sudden and sharp increase in imports of the PUC during the POI is an outcome of a combination of various global and domestic events, all of them unforeseen and unexpected. For purposes of clarity, these unforeseen and unexpected developments are briefly reiterated, as follows:

- (i) When faced with hindrances in exports to the EU and USA, China's huge production and excess capacities of the PUC which even otherwise is export oriented, had to find an alternative outlet, which they found in India;
- (ii) The imposition of protective measures on the PUC imported from China into the EU and USA shifted China's export focus towards India;
- (iii) The USA challenge to India's DCR under JNNSM resulting in the WTO Dispute Settlement Body holding the DCR to be inconsistent with Article III:4 of the GATT 1994 and Article 2.1 of the TRIMs Agreement, led to its withdrawal and consequential surge in imports to fill the space lost by the DI;

<sup>7</sup> Panel Report, *Ukraine – Passenger Cars*, para. 7.96. [ [http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/ukraine-passengercars\(panel\).pdf.download](http://www.worldtradelaw.net/reports/wtopanels/ukraine-passengercars(panel).pdf.download) ]

- (iv) India's commitment to the 2015 Paris Agreement paved the way for a domestic commitment to enhance the use of the PUC, which coupled with other events led to a surge in imports;
- (v) Declining landed price of the increasing imports of the PUC combined with other factors to change the competitive equation and place the DI at a disadvantage which was manifested in them i.e., the DI losing its share of the domestic market of the PUC to the imports; and
- (vi) India's obligations under GATT 1994 and the ITA-1 led to its Customs tariff on the imports of the PUC being made 'Free'.

5.8.10 As a result of the various aforementioned global and domestic unforeseen and unexpected developments, there has been an unquestionable verified surge in imports of the PUC into India. This surge in imports has significantly modified the competitive relationship between the imported and domestically produced PUC to the disadvantage of the DI.

### 5.9 Serious Injury and / or Threat of Serious Injury

5.9.1 The next matter for determination is whether the substantially increased imports of the PUC have caused and / or are threatening to cause serious injury to the Domestic Industry of like or directly competitive products. By its very nature this is a complex exercise as injury to the DI of the PUC is a function of various parameters like its share in the domestic market viz. a viz. imports; sales; production; capacity utilization, to name a few. Moreover, it is important that any negative parameter must not be a one-off event but it must display a consistent trend. Accordingly, various relevant parameters, as indicated below, are being examined to assess whether or not the increased imports of the PUC during the POI have caused and / or are threatening to cause serious injury to the Domestic Industry of like or directly competitive products.

- (i) **Share of domestic market:** Despite the rapid expansion in domestic demand, the market share of the DI has decreased; the DI had a market share of 13% in 2014-15 which declined to 7% during 2017-18 (A). During the same period, the market share of imports increased from 86% to 90%.

Market Share	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Imports	1,275 (86%)	4,186 (94%)	6,375 (89%)	4,737 (90%)	9,474 (90%)
Domestic sales by the applicants / DI	191 (13%)	276 (6%)	457 (6%)	358 (7%)	774 (7%)
Domestic sales by other Indian producers	9 (1%)	8 (0%)	325 (5%)	162 (3%)	325 (3%)
Total domestic sales by the DI	200 (14%)	284 (6%)	782 (11%)	520 (10%)	1,099 (10%)
Domestic Demand	1,476 (100%)	4,471 (100%)	7,157 (100%)	5,257 (100%)	10,573 (100%)

- (ii) **Sales:** The above table also reveals that sales of the domestic producers increased from 200 MW to 1,099 MW i.e. by 899 MW. However, it is material that while domestic sales increased by 899 MW, imports increased by 8,199 MW. Thus, the increase in imports was more than 9 times that of the increase in sales of the DI. Also, as the domestic demand increased from 1,476 MW in 2014-15 to 10,573 MW in 2017-18 (Annualized), it is clear that the increased imports of the PUC have substituted for the domestic production in meeting the domestic demand for the PUC.
- (iii) **Production:** Production of the DI increased from 237 MW in 2014-15 to 838 MW in 2017-18 (Annualized). There has also been significant addition of 1,000 MW to the installed capacity of the DI in 2017-18 (Annualized). However, despite this increase in installed capacity in 2017-18, the production that year increased by only 365 MW. Also, while the import volumes of the PUC have increased from 1,275 MW in 2014-15 to 9,474 MW in 2017-18 (Annualized) i.e., an increase of 643%, in comparison the production of DI increased 254% during the same period. This conclusion is based on the data in the table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (Upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Total imports	MW	1,275	4,186	6,375	4,737	9,474

Production of DI	MW	237	295	473	381	838
------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

- (iv) **Capacity utilisation** The capacity utilisation of the DI increased from 60% in 2014-15 to 78% in 2016-17 but fell down to 51% during 2017-18 (Annualized). Further, in 2017-18 (Annualized) itself, the production capacity was enhanced by 1,000 MW, but only 35% of this additional capacity was actually utilised, as shown in the table below. Even otherwise, the production facilities of the DI were grossly underutilised during the entire POI. Coupled with the increasing trend of imports of the PUC, this low level of capacity utilization is a clear indication of current injury and imminent threat of further injury to the DI.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Installed Capacity	MW	392	573	604	727	1,653
Production of DI	MW	237	295	473	381	838
Capacity Utilisation	%	60%	52%	78%	53%	51%

- (v) **Employment:** The employment generated by the DI has declined despite significant capacity addition. The recent entry of one applicant – M/s. Mundra Solar PV Ltd. (MSPVL) in May 2017 - has contributed to the overall increase in the total number of employees in the industry as a whole, but this is not reflective of the industry trend. In fact, if the number of employees of MSPVL is removed, the declining employment in the industry as a whole is evident. Further, as the Domestic Industry were and are operating far below their installed capacity [as seen at (iv) above] there has been a significant loss in potential employment opportunities.

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)
No. of employees excluding MSPVL (Indexed)	100	135	128	127
No. of actual employees (Indexed)	100	135	128	460

- (vi) **Productivity:** The trend of production per employee shows a declining trend throughout the period of investigation, as evident from the table below. It merits mention that even with the addition of a significant number of employees by the new entrant MSPVL in May 2017, the industry production did not increase proportionately. Per employee production was 0.316 MW during 2014-15, which fell down to 0.291 MW in 2015-16. Though this parameter rose to 0.492 MW in 2016-17, it declined again in 2017-18 to a low of only 0.243 MW. Thus, productivity (production per employee) was moving up and down and the current figures indicate a downturn that is likely to extend at least in the near future. It is clear that the DI have simply been unable to utilise their installed capacities to optimize productivity.

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Production of DI (MW)	237	295	472	381	838
No. of employees	749	1014	960	3445	3445
Productivity per employee (MW)	0.316	0.291	0.492	0.221	0.243

- (vii) **Profit / Loss** – The DI have incurred significant losses on domestic sales over the POI. The losses have more than doubled during 2017-18 (Annualized) compared to 2016-17, i.e. from 155 indexed units to 418 indexed units. Also, the Domestic Industry incurred an indexed loss of 418 during 2017-18 as compared to the base year of 2014-15. Such increase in losses has to be seen in the light of contrasting parameters such as the increase in capacity, increase in production and increase in domestic sales. Further, due to a significant decline in net sales realization, losses have compounded during 2017-18 (upto September, 2017) as compared to 2014-15.

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
Loss in Rs. Lakhs (Indexed)	100	351	155	187	418
Loss in Rs. Watt (Indexed)	100	243	65	100	103

- (viii) **Inventory:** The inventory carried by the DI increased by more than 4 times during the POI, as indicated in the table below.

Particulars	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)
Closing Inventory (Indexed)	100	82	152	411

- (ix) **Price Undercutting :** There was a significant price undercutting by the imported goods throughout the POI, as borne out from the table below. It is evident that the high level of price undercutting prevented the DI from increasing their prices to the break-even level as a result of which they suffered losses.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept. 2017)	2017-18 (Annualized)
<b>Landed value of imports</b>						
Solar Cells	Rs./Watt	18.78	18.81	15.42	14.04	14.04
Solar Modules	Rs./Watt	36.95	36.18	29.20	24.77	24.77
<b>Net sales realisation of Domestic Industry</b>						
Solar Cells (Indexed)	Rs./Watt	100	94	88	62	62
Solar Modules (indexed)	Rs./Watt	100	103	82	92	92
<b>Price Undercutting</b>						
Solar Cells (Indexed)	Rs./Watt	100	83	100	37	37
Solar Modules (Indexed)	Rs./Watt	100	173	121	458	458
<b>Price undercutting %</b>						
Solar Cells (Indexed)	%	100	83	122	49	49
Solar Modules (Indexed)	%	100	176	153	684	684

#### 5.10 Causal Link between Increased Import and Serious Injury / Threat of Serious Injury

5.10.1 The WTO Panel on *Korea-Dairy*<sup>8</sup> set forth the basic approach for determining “causation”, as follows:

*“In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a*

<sup>8</sup> WTO Panel on *Korea-Dairy*. Para VII.887 [[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds98\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds98_e.htm)]



*bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the Domestic Industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports. To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its Domestic Industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the Domestic Industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the Domestic Industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors."*

5.10.2 The analysis of data for the period 2014-15 to 2017-18 (upto Sept., 2017) indicates that imports of the PUC have remained at significantly higher levels and also the import prices of the PUC have come down drastically. This has led to the DI revising their own prices downwards. As a result, the net sales realization of the DI has sharply declined when compared to the base year, as detailed in the table under paragraph 5.9.1(ix) above

5.10.3 As a result of significant price undercutting by the imports, domestic selling prices saw significant price depression, as shown in the table below.

Particulars (Indexed)	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (upto Sept., 2017)	2017-18 (Annualized)
Selling price	Rs./watt	100	87	78	81	84
Price depression (Y-o-Y)	Rs./watt		100	66	(-)22	(-)47
Price depression (cumulative)	Rs./watt		100	166	145	119
Cost of sales	Rs./watt	100	109	76	82	83
Cost increase (Y-o-Y)	Rs./watt		100	(-)353	61	78
Price suppression (Y-o-Y)	Rs./watt		100	(-)124	16	10
Extent of prevention of price increase	Rs./watt	100	243	65	88	79

5.10.4 The following factors are also relevant in regard to determining the cause and effect relationship of increased imports and the serious injury during the POI and the threat of serious injury in the future, to the DI:

- (i) The volume of imports has increased significantly from 1275 MW to 9474 MW in absolute terms;
- (ii) The market share of imports has increased from 86% to 90% and, consequently, market share of the DI has declined from 13% to 7%;
- (iii) As the imports are available at prices lower than the selling price of the DI and are also decreasing over the time, the consumers are switching over to imported PUC with the effect that the DI are unable to not only sustain their prices but also have to face rising inventories (of the PUC);
- (iv) Another impact of the increased imports at low prices is that the DI are unable to increase their production and sales as compared to the rate of increase in demand / consumption of the PUC in India;
- (v) Though the DI established capacities to meet the growing demand for the PUC, the substantially increased imports at consistently reducing landed prices have led to idle production capacities, falling sales realization etc.; and
- (vi) The DI is incurring very heavy losses.

5.10.5 To sum up, a comprehensive evaluation of parameters enumerated above demonstrates that serious injury is being caused to the DI and is likely to continue in future by the significantly increased and continually increasing imports of the PUC. It is also relevant to note that while arriving at this conclusion, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on determining the causation of serious injury to the DI have been evaluated.

#### **(D) Critical Circumstances**

6. Rule 9 of the said Rules authorizes the Director General (Safeguards) to proceed expeditiously with the conduct of the investigation and in critical circumstances, record a preliminary finding regarding "serious injury" or 'threat of serious injury'. In terms of Rule 2(b) of the said Rules, the "critical circumstances mean circumstances in which there is clear evidence that imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to cause or threaten to cause serious injury to the DI and delay in imposition of provisional Safeguard Duty would cause irreparable damage to the DI.

6.1 As stated herein above, imports have taken place in such increased quantities and under such circumstances as to have already caused and further threatening to cause serious injury to the DI. The existence of critical circumstances are evaluated herein below.

- (i) The volume of imports of the PUC have risen significantly during the POI and still rising steadily and also the import prices are on the decline as shown in the table below. Further, imports of the PUC during each of the last two half yearly periods were significantly higher (2.7 times higher) than the imports during the first half of 2016-17. The import prices have also come down to Rs. 23.04 per watt during first half of 2017-18, a decline of over 23%. As import prices decline, ability of the DI to get remunerative prices also declines. As a consequence, sales and capacity utilization also suffer adversely.

Year	Import Quantity (MW)	Import Value (Rs. In Crores)	Import Price (Rs./Watt)
2016-17 (First Half)	1,720	5,158	30.00
2016-17 (Second Half)	4,656	12,375	26.58
2017-18 (First Half)	4,737	11,022	23.04

- (ii) On account of increasing and unabated imports of the PUC, the net sales realization of the DI declined sharply. Sales and capacity utilization also suffered adversely.
- (iii) The productivity per employee has declined sharply and the closing inventories have also increased.
- (iv) The domestic industry is incurring significant losses due to sharply declining import prices and the price undercutting is positive during the entire POI.

**6.2** It is clear that any delay in imposition of provisional Safeguard measures would cause further damage to the DI. Accordingly, I observe that critical circumstances very much exist warranting the immediate imposition of Safeguard measures.

**(E) Preliminary Findings**

**7.** To sum up, during the period of investigation there was an overall deterioration in the functioning of the DI. Moreover, the trend of the deteriorating parameters is indicative of the threat of serious injury continuing in the coming days. The parameter-wise finding of the serious injury suffered by the DI on account of enhanced imports of the PUC is summarized as under:

- (a) The volume of imports of the PUC have increased and are continuing to increase both in absolute and relative terms;
- (b) The DI's market share has declined, whereas the market share of imports has increased;
- (c) The increased imports of the PUC have substituted for the sales of the DI;
- (d) While the production of the DI has increased, their capacity utilization has decreased significantly;
- (e) Despite the increase in domestic demand for the PUC, the capacity utilization remained very low;
- (f) The DI are faced with a significant loss of potential employment opportunities;
- (g) The productivity per employee of the DI has shown a declining trend;
- (h) The DI are experiencing significant losses;
- (i) The inventories of the PUC have increased within the DI; and
- (j) The price undercutting by the imported PUC is positive throughout the POI.

**7.1** It is relevant to note that the DI continue to suffer serious injury and are facing further threat of serious injury. The trend in import volumes strongly suggests that imports of PUC are likely to increase in future due to excess capacity in China, export orientation of producers in China and opportunities lost by Chinese producers/exporters in other significant markets like USA and EU which would force such producers / exporters to target India. As the imported goods undercut the prices of Indian domestic industry to a significant degree, the DI would need time to restructure themselves to meet international competition. Otherwise, they would suffer further serious injury. Thus, an imminent threat of serious injury is also found in this case.

**7.2** In view of the above, my preliminary findings are that there is a direct correlation between the increase in imports and serious injury already suffered by the DI. Pertinently, all indicators exist to lead to the finding that the increased imports, which show no sign of abating and on the contrary are further increasing significantly, threaten to cause serious injury to the DI in the coming days. Thus, critical circumstances exist requiring imposition of provisional Safeguard Duty immediately in order to save the DI from further serious injury which would be difficult to repair, if the application of this Safeguard measure is delayed. These are, of course, preliminary findings on the basis of the documents and information on record and if any other factors that have a material bearing come to light during the course of investigation, they would be examined in detail in due course.

**(F) Developing Nations**

8. Proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975 provides that Safeguard Duty shall not be imposed on article originating from a developing country so long as its share of imports does not exceed 3% of the total imports of that article or, where the article is originating from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from all such developing countries, each with less than 3% import share taken together, does not exceed 9% of the total imports of that article. Further, Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016 specifies the developing countries for the purposes of this provision. Upon applying this legal provision read with the said notification to the available data in the present case, the finding is that import of the PUC is originating from more than one specified developing country including China PR and Malaysia. However, as a percentage of the total imports of the PUC into India, the imports from China PR and Malaysia individually account for more than 3% while the share of every other developing country is individually less than 3%. Also, the collective share of the developing countries whose individual share is less than 3% does not exceed 9% of the total imports of the PUC into India. Therefore, it must be held that the import of the PUC originating from developing countries (except China PR and Malaysia) will not attract Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

**(G) Coverage of Safeguard Measures**

9. As aforementioned, the applicants include SEZ units and they qualify to be treated as the DI. SEZ units are governed by the SEZ Act, 2005 and Section 30 thereof provides that any goods removed from a SEZ to the domestic tariff area shall be chargeable to duties of Customs including Safeguard Duty, where applicable, under the Customs Tariff Act, 1975. Thus, in the present case, if the PUC were to be cleared by an SEZ unit into the domestic market then any Safeguard Duty that is imposed on direct imports of the PUC into the country would get attracted on such clearances. The implication of this is that a portion of the DI that operates in SEZs would not only lose the protection of the Safeguard measure but to make matters worse, they would themselves be subjected to the said measure / levy. In other words, the application of Section 30 of the SEZ Act, 2005 would negate the imposition of Safeguard measures under Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 and be counter-productive. The remedy to this could be a duty exemption to the extent of the Safeguard measure when the PUC is cleared by a SEZ unit into the domestic market. This would maintain the relevance of the Safeguard measures in the interest of the DI. This would also satisfy the cannon of equity by placing all domestic producers or all constituents of the DI at par with regard to the applicability of the Safeguard measures on the imported PUC. However, this matter falls outside the ambit of the present proceedings which are governed strictly by the provisions of the Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 read with its Rules and is, therefore, left for the consideration of the Government. Needless to state, the provisions of Section 8B(2A)(ii) of the Customs Tariff Act, 1975 dealing with the levy of Safeguard Duty, if an article subjected to a Safeguard Duty on import is cleared as such from the SEZ into the domestic market or is used in the manufacture of any goods that are cleared by the SEZ unit into the domestic tariff area would apply.

**(H) Recommendations**

10. In view of the aforementioned analyses and findings, I find that the product under consideration viz. "Solar Cells whether or not assembled in modules or panels" is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the DI manufacturing like or directly competitive products. I also find that existing critical circumstances justify the immediate imposition of a provisional Safeguard Duty in order to save the DI from further serious injury, which would be difficult to repair, if the application of the recommended Safeguard measure is delayed. Accordingly, I make the following recommendations:

- (i) I recommend that pending a final determination, considering the average cost of sales by the Domestic Industry arrived at on the basis of import quantity ratio of Solar cells and Solar modules (confidential), a reasonable return on the cost of sales excluding interest, the present level of import duties, and the present average import prices, a provisional Safeguard Duty be imposed at the rate of 70% (Seventy percent) *ad valorem* on the imports of the PUC viz. "Solar Cells whether or not assembled in modules or panels" falling under Customs Tariff Item 85414011 of the Customs Tariff Act, 1975 from all countries with the exception of the developing countries indicated in clause (iii) below. The Tariff Item mentioned herein is indicative only and the description of the imported goods will determine the applicability of the recommended Safeguard Duty.
- (ii) I also recommend that the provisional Safeguard Duty on the import of the said product, as above, be levied for a period of 200 days (two hundred days), which is considered to be the minimum period of time required to protect the interests of the Domestic Industry.
- (iii) As the imports from the developing countries listed in Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016, other than China PR and Malaysia, do not exceed 3% individually and 9% collectively, the imports of "Solar Cells whether or not assembled in modules or panels" originating from such developing countries (other than China PR and Malaysia) will not attract the recommended provisional Safeguard Duty in terms of proviso to Section 8B(1) of the Customs Tariff Act, 1975.

**(I) Further Process**

**11.** The information provided by various parties may be subjected to verification where necessary, for which they will be informed separately. This preliminary finding is borne out from the data submitted by the DI (as indicated above) and it would be subject to further investigation by the authority.

**11.1** A public hearing will be held in due course before making a final determination, for which the date will be informed separately.

[F. No. 22011/68/2017]

SANDEEP M. BHATNAGAR, Director General